

गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में दी जानकारी

नई दिल्ली। देश में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में लिखित जानकारी देते हुए बताया कि 2021 से 2025 के बीच साइबर फ्राड करने वाले अपराधियों ने लोगों के खातों से 55,000 करोड़ से ज्यादा की रकम उड़ा ली. मंत्रालय के मुताबिक पिछले पांच सालों में कुल 6 करोड़ 58 लाख 9063 शिकायतें साइबर ठगी से जुड़ी दर्ज की गईं. रिपोर्ट में बताया गया कि अकेले 2025 में ही साइबर ठगों ने 22,495 करोड़ की ठगी की. इसी साल 24 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. शिकायतों में हर साल बढ़ा उछाल देखने को मिला.



DBD

दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिप्सांसिबिलिटी है

साइबर ठगी का मायाजाल

55,000 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी

2021 से 2025 तक शिकायतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

सरकार कैसे रोक रही है साइबर क्राइम

इन सवालों के जवाब में गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को अलग-अलग तरह से मदद करती है. उन्होंने बताया कि उनके मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) का गठन किया है. यह आई4सी ही देश में साइबर क्राइम से निपटने में मदद करता है. इसी के तहत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) की शुरुआत की गई थी. इसमें लोग साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसमें

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों को प्राथमिकता दी जाती है. गृह राज्यमंत्री के मुताबिक आई4सी के तहत सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्राड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम को 2021 में शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य वित्ति फ्राड की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा पैसा इधर से उधर करने पर रोक लगाना है. सरकार के मुताबिक इस पर दर्ज कराए गए 23 लाख 62 हजार मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों के आठ हजार 189 करोड़ रुपये बचाए गए हैं.

| साल | शिकायतों की संख्या | कितने करोड़ का फ्राड |
|------|--------------------|----------------------|
| 2021 | 2,62,846 | 551 |
| 2022 | 6,94,446 | 2290 |
| 2023 | 13,10,357 | 7465 |
| 2024 | 19,18,835 | 22848 |
| 2025 | 24,02,579 | 22495 |

साइबर ठगी के मामलों में लगातार हुई बढ़ोतरी

रिपोर्ट के अनुसार ठगी की रकम भी लगातार बढ़ी. 2021 में 551 करोड़, 2022 में 2,290 करोड़, 2023 में 7,465 करोड़, 2024 में 22,848 करोड़ और 2025 में 22,495 करोड़ की ठगी रिपोर्ट हुई. हालांकि मंत्रालय ने बताया कि I4C सिस्टम की मदद से 2025 में 8,189 करोड़ की रकम को साइबर फ्राड होने से बचाया भी गया.

55,000 करोड़ से ज्यादा की रकम उड़ाई

साल 2021 में 2,62,846 शिकायतें दर्ज हुईं, जो 2022 में बढ़कर 6,94,446 हो गईं. 2023 में यह संख्या 13,10,357 तक पहुंची. 2024 में 19,18,835 शिकायतें दर्ज हुईं और 2025 में यह आंकड़ा 24,02,579 हो गया.

देश में कितने हैं नेशनल डिजिटल इवेस्टीगेशन सपोर्ट सेंटर

सरकार ने बताया है कि आई 4 सी के तहत 2009 में नेशनल डिजिटल इवेस्टीगेशन सपोर्ट सेंटर की स्थापना दिल्ली में की गई है. पहले इसे नेशनल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी के नाम से जाना जाता था. इसी तरह की एक लैबोरेटरी अगस्त 2025 से असम में काम कर रही है. इनका मकसद राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के जांच अधिकारियों की उनकी जांच में मदद करना है. इसके नई दिल्ली केंद्र ने 31 दिसंबर 2025 तक साइबर क्राइम के 13 हजार 299 मामलों में राज्यों और केंद्रशासित राज्यों की मदद की है. इसके अलावा केंद्र सरकार राज्य सरकारों के फॉरेंसिक साइंस लैब के उन्नयन में भी मदद कर रही है.

ब्रीफ न्यूज़

देश का पहला 'जाति मुक्त' गांव घोषित हुआ सौदला

अहिल्यानगर। देश में जहां एक ओर जातिगत जनगणना और आरक्षण की राजनीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के एक छोटे से गांव 'सौदला' ने एक ऐसी पहल की है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। सौदला ग्रामसभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर खुद को 'जाति मुक्त' घोषित कर दिया है। अब इस गांव के लोग अपने नाम के आगे जातिपूर्वक उपनाम (सरनेम) का प्रयोग नहीं करेंगे। पांच फरवरी को ग्राम प्रधान शरद बाबुराव अग्रवाई की अध्यक्षता में आयोजित 'विशेष ग्राम सभा' की बैठक में यह क्रान्तिकारी निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि गांव में अब किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी सामाजिक कार्यक्रम में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों का मानना है कि जाति व्यवस्था केवल समाज को बांटने का काम करती है, जबकि विकास के लिए एकता अनिवार्य है।

एसटी बस पलटने से 14 छात्रों सहित 18 घायल



पुणे। ओतुर स्थित कल्याण-अहमद नगर रोड पर गुरुवार दोपहर करीब 12.00 बजे एक एसटी बस पलट जाने से 14 छात्रों सहित 18 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 शिक्षक भी हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओतुर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक लहु थाटे ने बताया कि अहिल्या नगर के नेवासा में स्थित एक जिला परिषद स्कूल के 53 छात्रों को लेकर बस शिवनेरी किले की ओर जा रही थी। अचानक ओतुर में बस चालक का नियंत्रण बिगड़ जाने से बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। घायल छात्रों की पहचान श्रवणी नवथार, कुष्णा नवथार, सिद्धांत मुसाळे, सार्थक कोकाटे, जिया शेख, ईश्वरी लहरे, सागर फावले, अनुराज काले, रितेश मोरे, स्नेहल खंडगले, शुभम गोंडले, पायल कचरे, काव्या गोसावी, आयरन नवथार के रूप में की गई है।

अभ्यारण्यों के बाहर बाघ प्रबंधन के लिए 5.40 करोड़ की मंजूरी

मुंबई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने महाराष्ट्र में नामित बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रह रहे बाघों के प्रबंधन के लिए पहली बार विशेष रूप से धनराशि स्वीकृत की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, 10 फरवरी को 'बाघ अभ्यारण्यों के बाहर बाघों का प्रबंधन: मानव-बाघ संघर्ष से निपटने की रणनीतियाँ' परियोजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 5.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है। यह धनराशि राज्य के छह वन प्रभागों को प्रदान की जाएगी।

जिम्मेदारी की आवाज़ का अवसान

- प्रख्यात समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी नहीं रहीं
- उन्होंने ही पढ़ा था रंगीन दूरदर्शन का पहला समाचार

हमने सरला माहेश्वरी से सीखने की कोशिश की हताश, परेशान, अस्त-व्यस्त-पस्त जनमानस के बीच बोली

जानेवाली सादगी, संयम और संजीदगी की भाषा। हमने सरला माहेश्वरी से सीखने की कोशिश की सौम्य मुस्कान, संयमित आवाज और नपु-ली प्रस्तुति के साथ कैसे पढ़ी जाए खबर। सरला माहेश्वरी मूलतः एक न्यूज़ रीडर रही। वह वो दौर था जब एंकर का मतलब तेज आवाज या भौंचक चेहरा नहीं था, बल्कि एक भरोसेमंद आवाज थी जो दर्शकों तक खबरों को ईमानदारी से पहुँचाती थी। चेहरे पर शांति, भाषा में मर्यादा और बातों में भरोसा। आज के कर्करा, आत्मधन्य और रंगीन टीवी की दुनिया में सरला माहेश्वरी की सादगी, संयम और संजीदगी का अभाव है। आज का टीवी प्रस्तुति के साथ कैसे पढ़ी जाए खबर। सरला माहेश्वरी मूलतः एक न्यूज़ रीडर की विदाई नहीं, बल्कि उस युग की विदाई है जहाँ पत्रकारिता एक जिम्मेदारी थी, न कि महज एक 'परफॉर्मेंस'। उन्हें याद रखना जरूरी है — ताकि जब अगली पीढ़ी पत्रकारिता को केवल टीआरपी का खेल मानने लगे, तो सरला माहेश्वरी जैसी आवाजें उनके संदर्भ की तरह मौजूद रहें।



तीन दशकों तक समाचार जगत में छोड़ी अमिट छाप

रिपोर्टर्स के मुताबिक सरला माहेश्वरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी करने के बाद बतौर एंकर अपना करियर शुरू किया था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के दौर में अपना करियर शुरू करने वाली सरला ने टीवी को रंगीन प्रसारण में बदलते देखा। उन्होंने करीब तीन दशक तक भारतीय समाचार जगत में उल्लेखनीय योगदान दिया।

एजेंसी | नई दिल्ली

दूरदर्शन की प्रख्यात पूर्व समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी नहीं रहीं। 71 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर दूरदर्शन, साथी समाचार वाचकों समेत प्रशासकों ने गहरा दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी है। दूरदर्शन में सरला माहेश्वरी के साथी समाचार वाचक रहे शम्मी नारंग ने गुरुवार को उनके निधन की जानकारी दी। सोशल मीडिया मंच एक्स और इंस्टाग्राम पर नारंग ने एक पोस्ट में लिखा, 'मुझे दूरदर्शन में अपनी एक्स को-न्यूज़ एंकर, सरला माहेश्वरी के दुखद निधन की अनाउंसमेंट करते हुए बहुत दुख हो रहा है।'

दूरदर्शन ने क्या कहा?

दूरदर्शन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा 'दूरदर्शन परिवार की ओर से श्रीमती सरला माहेश्वरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वह दूरदर्शन की सम्मानित और प्रतिष्ठित समाचार वाचिका थीं, जिन्होंने अपनी सौम्य आवाज, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण प्रस्तुति से भारतीय समाचार जगत में विशेष स्थान बनाया। उनकी सादगी, संयम और व्यवित्तव ने दर्शकों के मन में गहरा विश्वास स्थापित किया।

साथी एंकरों ने दी श्रद्धांजलि

शम्मी नारंग ने लिखा, 'वह सिर्फ दिखने में ही नहीं दिल से भी बहुत खूबसूरत थीं। वह ज्ञान का भंडार थीं। दूरदर्शन स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी का एक अलग ही 'ऑन' था। वह सभी का सम्मान करती थीं और जिस भी जगह का वह हिस्सा थीं, उसे ऊपर उठाती थीं।' उनकी साथी समाचार वाचिका रही शीला चमन ने एक्स पर लिखा, 'मेरी प्रिय दोस्त और मेरी हालिया पुस्तक दूरदर्शन डायरीज की सहलेखिका सरला के निधन की सूचना दुखद है। उनके चेहरे की मुस्कान, हमारी बातचीत और दूरदर्शन में साथ बिताया समय हमेशा याद रहेगा।' पूर्व समाचार वाचिका रिनी सिमोन खन्ना ने लिखा, 'सरला उत्कृष्टता की मिसाल थीं। सरला, शिष्टता के साथ उन्होंने हर किसी के मन में अपने प्रति सम्मान का भाव विकसित किया। मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी।' इनके अलावा विभिन्न समाचार चैनलों, समाचार पत्रों, मीडिया जगत से जुड़ी हस्तियों और राजनीतिक दलों ने भी सरला माहेश्वरी के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

रोहित पवार के समर्थन में अमोल मिटकरी

बाहरी संस्था से अजीत हादसे की जांच कराने की मांग

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार के विमान हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने इस मामले की जांच में विदेशी एजेंसियों को शामिल करने की मांग की है। अब रोहित पवार की इस मांग का एनसीपी (एपी) विधायक अमोल मिटकरी ने भी समर्थन किया है।



मितकरी ने कहा है कि मैंने पहले जो शक जताया था, उसमें कुछ सच्चाई नजर आ रही है। इसलिए बाहरी संस्था से भी जांच कराने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात की और पत्र साँपा

मितकरी ने मांग की है कि संबंधित मामले की तुरंत किसी बाहरी संस्था से जांच कराई जाए। लोगों में पैदा हुए संदेह को दूर करने और सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र साँपा है। रोहित पवार ने हाल में मुंबई और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विमान हादसे पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीआईडी के अलावा केंद्रीय व विदेशी एजेंसियों को भी जांच प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की है। साथ ही उनकी मांग है कि अजीत पवार के परिवार वालों को भी जांच प्रक्रिया शामिल में शामिल किया जाए। रोहित का मिटकरी ने समर्थन करते हुए कहा है कि रोहित पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे उठाए हैं, उसमें सच्चाई नजर आ रही है। मैंने भी ये संदेह जताए थे।

मुझे खत्म करने की दी गई सुपारी : जरांगे

सोलापुर। मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन चुके कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने एक सार्वजनिक मंच से अपनी जान को खतरा होने का दावा कर महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी है। सोलापुर जिले के पंढरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जरांगे ने आरोप लगाया कि मराठा समुदाय का भलाई और हक के लिए किए जा रहे उनके संघर्ष के कारण कुछ लोग उन्हें अपना



कट्टर दुश्मन मान बैठे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें खत्म करने के लिए 'सुपारी' (हत्या का ठेका) दी जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि उनके आंदोलन से कुछ प्रभावशाली गुट असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जरांगे ने केवल अपनी जान का खतरा ही नहीं बताया, बल्कि अपने आंदोलन को भीतर से कमजोर करने की साजिश का भी जिक्र किया।

न्यायिक खबर जब तक भारत नहीं लौटता, उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं: कोर्ट

विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकारा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि जब तक माल्या व्यक्तिगत रूप से भारत लौटकर कानून के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता, तब तक उसकी किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने माल्या के वकील को दो दृक शब्दों में कहा कि एक भगोड़ा अपराधी देश की न्याय प्रणाली का साथ दूर बैठकर नहीं उठा सकता। विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका में उसने विशेष अदालत द्वारा उसे 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' (FEO) घोषित किए जाने के आदेश को चुनौती दी है, जबकि दूसरी याचिका में उसने 2018 के भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर ही सवाल खड़े किए हैं।



2019 से भगोड़ा घोषित है माल्या

70 वर्षीय शराब कारोबारी विजय माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहा है। भारतीय बैंकों के साथ हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद, जनवरी 2019 में प्रिवियुअर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की विशेष अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।

हलफनामे के जरिए वापसी की मंशा साफ करने का निर्देश

अदालत ने माल्या के वकील को निर्देश दिया है कि वह एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हो कि माल्या भारत कब लौटेंगे। पीठ ने कहा कि हमें यह रिकॉर्ड पर दर्ज करना पड़ सकता है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर अदालत की प्रक्रिया से बच रहा है। अदालत ने निष्पक्षता बरतते हुए फिलहाल याचिकाओं को खारिज तो नहीं किया है।

लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक पर ईडी का शिकंजा

85 करोड़ के हेरफेर में गिरफ्तारी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोढ़ा को 85 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी का आरोप है कि राजेंद्र लोढ़ा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी को करोड़ों का चूना लगाया और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की।



जेल से ही लिया गया हिरासत में

राजेंद्र लोढ़ा पहले से ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में पिछले साल सितंबर से न्यायिक हिरासत में थे। गुरुवार को ईडी ने उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को उन्हें रिमांड के लिए दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर के आधार पर की गई है।

क्या है पूरा मामला?

जांच में सामने आया है कि 2015 में कंपनी के निदेशक बने राजेंद्र लोढ़ा के पास केवल जमीन अधिग्रहण के सीमित अधिकार थे। लेकिन उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कई अनधिकृत सोदे किए। ईडी का दावा है कि राजेंद्र ने अपने बेटे साहिल लोढ़ा और करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर कंपनी के पैसे के गबन की साजिश रची। फर्जी कब्जेदार दिखाए गए, मगनदत्त समझौते बनाए गए और कंपनी के फंड को नकद में निकाला गया। उन्होंने कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल अपने और परिवार के निजी लाभ के लिए किया और बिना किसी हक के अपने सहयोगियों को सस्ते में प्लेट आवंटित किए।

10 करोड़ की जमीन मात्र 48 लाख रुपये में बेची

घोटाले का सबसे चौकाने वाला पहलू जमीनों की खरीद-फरोखत में सामने आया है। ईडी ने बताया कि पनवेल में कंपनी की 4, 150 वर्ग मीटर जमीन, जिसका बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपये था, उसे एक फर्जी कंपनी को महज 48 लाख रुपये में बेच दिया गया। इससे कंपनी को सीधे तौर पर 9.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसके अलावा, 'उषा प्रॉपर्टीज' और 'श्रीराम रियल्टीज' जैसी मुछौटा कंपनियों के जरिए पहले जमीन खरीदी गई और बाद में उसे लोढ़ा डेवलपर्स को बहुत ऊंची कीमतों पर बेचा गया। जांच एजेंसी को एक और गंभीर मामला मिला है। 2013 में कंपनी के कर्मचारी मंगेश पुराणिक के नाम पर जमीन खरीदी गई थी। मंगेश की मौत के बाद, उस जमीन को धोखे से लोढ़ा के सहयोगियों के नाम ट्रांसफर किया गया और फिर भारी मुनाफे पर वापस कंपनी को बेच दिया गया। ईडी के मुताबिक, इन सभी हथकंडों से कंपनी को कुल 85 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

नाले के ऊपर ही स्वास्थ्य केंद्र

दोषियों की तलाश में जुटा प्रशासन

विनय दूबे | भाईदर

मीरा भाईदर मनपा (एमबीएमसी) के आरोग्य विभाग और घनकचरा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोग्य केंद्र के पीछे स्थित खुले नाले से भारी मात्रा में मरी मुर्गियों और मटन के अवशेष मिलने से नागरिकों की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लग गया है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार नाले के समीप आरोग्य केंद्र संचालित करना स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता केतन बारिया नवनिर्मित आरोग्य

आरोग्य केंद्र के पीछे नाले से 3 टन मरी मुर्गियों के अवशेष बरामद



केंद्र में पहुंचे थे, जहां आसपास फैली तीव्र दुर्गंध से वे अस्वस्थ हो गए। जांच के लिए जब उन्होंने केंद्र के पीछे बह रहे खुले नाले में देखा तो पूरा नाला चिकन और मटन के अवशेषों से भरा मिला। इसकी शिकायत महापौर से की गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मनपा प्रशासन ने नाले की

सफाई कर लगभग 3 टन चिकन और मटन कचरा निकालकर उक्त स्थित डंपिंग ग्राउंड में ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण किया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से खड़ी चिकन की पांच गाड़ियों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।



प्रभाग अधिकारी का बयान

प्रभाग क्रमांक 5 के प्रभाग अधिकारी जितेंद्र कांबले ने बताया कि नाले की सफाई पूरी कर ली गई है। यातायात विभाग को पत्र लिखकर अवैध रूप से खड़ी निजी वाहनों के खिलाफ लगातार दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है।

आरटीआई कार्यकर्ता ने उठाए सवाल

केतन बारिया ने एमबीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान केवल जागरूकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ठोस कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि चिकन और मटन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए और अवैज्ञानिक ढंग से कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उनका आरोप है कि खुले नाले को यथावत रखकर मनपा स्थानीय नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है।

सेवाकर्मी पुरस्कार में ठाणे जिला परिषद को 80 प्रतिशत अंक

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित 'सेवाकर्मी पुरस्कार' कार्यक्रम के तहत राज्यभर के कार्यालयों के कामकाज का मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन में ठाणे जिला परिषद ने 100 में से 80 अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य की सात जिला परिषदों—सोलापुर, पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, सतारा, ठाणे और सांगली—ने 80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। ठाणे जिला परिषद का इस सूची में शामिल होना जिले के लिए गौरव की बात मानी जा रही है।



ठाणे जिला परिषद की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मूल्यांकन में प्रशासनिक कार्यप्रणाली, सेवा पंजीयन प्रबंधन, कर्मचारी सेवा विषयक पारदर्शिता, रिकॉर्ड का समय पर संधारण, सरकारी सेवा नियमों का पालन और कार्यालयीन कार्य में अनुशासन व गुणवत्ता जैसे पहलुओं को महत्व दिया गया।

डिजिटलीकरण और प्रशिक्षण में प्रगति

गुप-सी और गुप-डी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का कंप्यूटरीकरण, समय पर वरिष्ठता सूची का प्रकाशन, भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में नियमानुसार नियुक्तियों, तथा iGOT (कर्मयोगी) पोर्टल पर प्रशिक्षण पूर्ण करने जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति दर्ज की गई। कर्मचारी प्रबंधन में पारदर्शिता और केंद्र आधारित जानकारी के सुव्यवस्थित संकलन को भी महत्वपूर्ण माना गया। जिला परिषद को कार्यालयीन कार्य में सुसुत्रता, ई-प्रणाली के प्रभावी उपयोग और कर्मचारियों से जुड़े मामलों के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निपटारे के लिए उच्च अंक प्राप्त हुए। इस सफलता के पीछे अधिकारियों और कर्मचारियों का समन्वय, प्रशासनिक अनुशासन और सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को अहम बताया गया है।

वैतरणा नदी में गिरे युवक की बची जान



डीबीडी संवाददाता | पालघर

जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना में 25 वर्षीय उदय मंगेश वांगड लोकल ट्रेन से फिसलकर वैतरणा नदी में गिर गया, लेकिन रेलवे कर्मचारी की तत्परता से उसे सुरक्षित बचा लिया गया। यह हादसा मंगलवार रात उस समय हुआ जब उदय बोइंगर से बोरीवली जा रहा था और ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होने के दौरान पुल पार करते समय उसका संतुलन बिगड़ गया। गनीमत रही कि वहां पटरी के रखरखाव के लिए तैनात रेलकर्म रमेश सिंह ने उसे गिरते हुए देख लिया और बिना समय गंवाए शोर मचाते हुए ग्रामीणों व अधिकारियों को इसकी सूचना दी। रमेश सिंह की सूचना पर दो स्थानीय ग्रामीण तुरंत अपनी नाव लेकर नदी के बीचों-बीच पहुंचे, जहां उदय पुल के खंभे से निकली एक लोहे की छड़ के सहारे टिका हुआ था। ग्रामीणों ने उसे सुरक्षित नाव में बैठाकर किनारे पहुंचाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

क्राइम ब्रांच कल्याण सर्कल ने हासिल किया पहला स्थान

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत क्राइम ब्रांच के कल्याण सर्कल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि से पूरे ठाणे शहर में पुलिस विभाग पर गर्व जाता जा रहा है। खाकी वर्दी में तैनात अधिकारियों और जवानों ने न केवल उल्लेखनीय आंकड़े दर्ज किए, बल्कि जनता का सुरक्षा पर भरोसा भी मजबूत किया है। यह सफलता पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे के मार्गदर्शन और सर्कल-3 के पुलिस उपायुक्त अतुल जेंडे के नेतृत्व में मिली है। पिछले वर्ष 3 हजार से अधिक अपराधों का सफलतापूर्वक

3 हजार से अधिक मामलों का खुलासा



खुलासा कर कल्याण सर्कल ने जांच में तेजी, सटीकता और बेहतर समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

जनता में बढ़ा सुरक्षा का भरोसा

यह उपलब्धि केवल मामलों के निपटारे तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई परिवारों को न्याय मिला है और क्षेत्र में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। दिन-रात, त्योहारों की भीड़ या प्रतिकूल मौसम—हर परिस्थिति में पुलिस बल अपनी जिम्मेदारी पर उठा रहा। इस सफलता में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों, जांच अधिकारियों और सभी पुलिसकर्मियों की मेहनत और अनुशासन का अहम योगदान रहा है। अपराधियों की धरपकड़ में दिखाई गई तत्परता और पेशेवराना कार्यशैली ने विभाग की साख को और मजबूत किया है।

बीच-बचाव करना पड़ा महंगा डोसा कॉर्नर मालिक पर चाकू से हमला



डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

कैप-5 के कुर्ला कैप चौक स्थित बिट्टू डोसा कॉर्नर के बाहर हो रहे झगड़े में बीच-बचाव करना दुकान मालिक को भारी पड़ गया। झगड़ा शांत कराने गए मालिक और उनके मित्र पर आरोपियों ने बेरहमी से हमला कर चाकू मार दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का उल्हासनगर के शासकीय अस्पताल में उपचार जारी है। मंगलवार रात करीब साढ़े दस बजे डोसा कॉर्नर के मालिक बबलू आवला अपने कामगारों के साथ दुकान बंद कर साफ-सफाई कर रहे थे। उसी समय दुकान के बाहर उनके परिचित युवक पुनारी और करण किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे थे।

बीच-बचाव के दौरान किया हमला

झगड़ा बढ़ता देख बबलू आवला ने दोनों को दूसरी जगह जाकर बात करने की सलाह दी। इस पर नाराज होकर आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया और बबलू आवला तथा उनके मित्र राहुल चव्हाण पर चाकू, कुर्सी और हाथ के कड़े से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से जखमी हो गए।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बबलू आवला की शिकायत पर हिलालाइन पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

राजस्व अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता | पालघर

जिले की जव्दार तहसील में भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पालघर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने दो सरकारी अधिकारियों को रोये हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों की पहचान सच्चा-जामसर के ग्राम राजस्व अधिकारी गजानन नागेश चौहरे और सच्चा-हिरडण्डा के ग्राम राजस्व अधिकारी सीताराम विष्णु इंधन के रूप में हुई है। इन दोनों अधिकारियों को कल 11 फरवरी 2026 को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया गया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति के तहत पालघर ब्यूरो द्वारा की गई है।



पीएम आवास योजना के लाभार्थी से वसूली का खेल

इस मामले की पुष्टि में प्रधानमंत्री आवास योजना जुड़ी हुई है। शिकायतकर्ता को इस योजना के तहत घर बनाने की मंजूरी मिली थी, जिसके लिए वह 10 फरवरी को लेंडी नदी से रेत निकाल रहा था। दादर कोपरा गांव के पास इन दोनों राजस्व अधिकारियों ने पटवारी के साथ मिलकर ट्रैक्टर रोका और अवैध रेत उखलाने की कार्रवाई का डर दिखाकर 40,000 रुपए की मांग की। डरे हुए शिकायतकर्ता ने तुरंत 20,000 रुपए दे दिए।

मियावाकी जंगल की पुकार सुनो सरकार

मुझे शौचालय बनने से बचाओ...

डीबीडी संवाददाता | भाईदर

पर्यावरण संतुलन के उद्देश्य से मनपा द्वारा निर्मित शहर का पहला मियावाकी जंगल इन दिनों अधिकारियों की अनदेखी के कारण दुर्गंध का स्रोत बनता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने वन परिसर में फैल रही गंदगी और बदबू को लेकर नाराजगी जताई है। इस गंभीर मुद्दे को 10 दिसम्बर 2025 को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वायु प्रदूषण कम करने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और जैव विविधता बढ़ाने के उद्देश्य से शहर में तीन मियावाकी जंगल विकसित किए गए हैं। मीरा रोड के इंदरलो फेज-3 स्थित आरक्षण क्रमांक 230 में 5 मार्च 2022 को तत्कालीन मनपा आयुक्त/प्रशासक दिलीप ढोले द्वारा इस वन का उद्घाटन किया गया था। ग्रीन यात्रा नामक सामाजिक संस्था के सहयोग से विभिन्न प्रजातियों के 10,500 पौधे लगाए गए थे, जो आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं। लगभग 28,000 वर्ग फुट में फैले इस जंगल में 55 से अधिक प्रजातियों के पेड़ हैं और यहां पक्षियों का बसेरा भी है।

सुरक्षा दीवार अधूरी, कूड़े के ढेर से बिगाड़ रहा पर्यावरण संतुलन



प्रशासन ने दिया आश्वासन

उपायुक्त सचिन बांगर ने कहा कि प्रशासन स्वच्छता को लेकर गंभीर है, लेकिन नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे परिसर को साफ रखें। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही जंगल में जमा कूड़ा साफ कराया जाएगा और अधूरी सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि इस मियावाकी जंगल को बचाने के लिए त्वरित और ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि यह पर्यावरण संरक्षण के अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर सके।

अधूरी दीवार से बढ़ी समस्या

वन के चारों ओर बनाई जाने वाली सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके कारण यहां कूड़ा-कचरा फेंका जाने लगा है। परिणामस्वरूप स्वच्छ हवा देने वाला यह जंगल अब बदबू फैलाने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते उचित रखरखाव नहीं किया गया तो अतिक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है।

सांख्यिक सूचना

नायागंव स्टेशन पर यात्रियों हेतु फुट ओवर ब्रिज (FOB) बंद रहेगा

एमआरवीसी (MRVC) द्वारा नायागंव स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज (FOB) एवं प्लेटफॉर्म के निर्माण/विस्तार का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के संबंध में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 को प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 एवं 3 से जोड़ने वाला मौजूदा उबरी फुट ओवर ब्रिज (FOB) यात्रियों के लिए डेढ़ माह की अवधि हेतु बंद रखा जाएगा। इस अवधि के दौरान यात्री निम्न वैकल्पिक सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं: एक 10 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, दो 6.0 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज, एक 6 मीटर चौड़ा सवारी, उपरोक्त के अनुसार, संबंधित फुट ओवर ब्रिज दिनांक 14.02.2026 से बंद रहेगा। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है।

पश्चिम रेलवे
www.indianrailways.gov.in

अंबिका नगर में पानी की कमी

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे के वागले इस्टेट स्थित अंबिका नगर परिसर में पिछले कई दिनों से भीषण जल संकट बना हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। मनपा के जल आपूर्ति विभाग की कथित लापरवाही के कारण नलों से पानी गायब है, जबकि नागरिक नियमित रूप से अपने पानी के बिलों का भुगतान कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद विभाग केवल खोखले वादे कर रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि हफ्ते में केवल एक या दो बार पानी मिल रहा है, जिसके कारण महिलाओं और बुजुर्गों को पानी की तलाश में दूसरी चॉलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी सेहत और सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है।

रेगुलर पानी के बिल भरने के बाद भी नल सूखे



एक या दो बार पानी मिल रहा है, जिसके कारण महिलाओं और बुजुर्गों को पानी की तलाश में दूसरी चॉलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी सेहत और सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है।

जन आक्रोश और विभाग का आश्वासन

प्रशासन के प्रति बढ़ते गुस्से के बीच नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। लोगों का कहना है कि प्रशासन 'पानी नहीं, पर बिल भरने पर' की नीति अपना रहा है, जो उनकी जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करता है। इस गंभीर समस्या पर प्रतिक्रिया देते हुए वागले प्रभाग समिति के डिप्टी इंजीनियर माधव जांगड़े ने आश्वासन दिया है कि अंबिका नगर में जल आपूर्ति सुधारने के लिए जल्द ही नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी।

कल्याण-शिलफाटा सर्कल पर टेम्पो में लगी भीषण आग



डीबीडी संवाददाता | ठाणे

कल्याण-शिलफाटा सर्कल इलाके में गुरुवार दोपहर एक टेम्पो में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। समय पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। ठाणे मनपा आपदा प्रबंधन को दोपहर करीब 3:35 बजे शिल फायर स्टेशन से सूचना मिली कि शिल-दिवा क्षेत्र में महापे से उत्तरशिव

जाने वाली सड़क पर एक टेम्पो में आग लगी है। टेम्पो के मालिक व चालक जहर अहमद वाहन लेकर महापे से उत्तरशिव की ओर जा रहे थे। टेम्पो में प्लास्टिक के ड्रम और कलर पाउडर सहित अन्य सामग्री लदी हुई थी। आग लगते ही चालक ने तत्काल वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और सुरक्षित बाहर निकल गया। उसकी संतर्कता के कारण एक संभावित बड़ा हादसा टल गया।

20 मिनट में आग पर काबू

शिल फायर स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर सरनोबत के नेतृत्व में दमकल कर्मी एक फायर इंजन के साथ मौके पर पहुंचे। डाइरर ट्रैफिक पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर मौजूद रही। दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और लगभग 3:55 बजे तक आग पूरी तरह बुझा दी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

क्रिकेट टूर्नामेंट में 'बाहरी' बताकर युवक की पिटाई

तीन आरोपियों पर मामला दर्ज

डीबीडी संवाददाता | रत्नागिरि

रत्नागिरि जिले में एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट में 'बाहरी' होने का आरोप लगाकर तीन लोगों द्वारा एक व्यक्ति की कथित तौर पर पिटाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधस्वतिवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के अनुसार, रविवार तड़के गुहागर के आरे इलाके में जयेश जनार्दन खोत (36) पर हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल खोत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों के मुताबिक वह अब खतरे से बाहर है। खोत, जो ठाणे के कल्याण में रहता है और रैंपिडो में काम करता है, अपने पैतृक गांव गुहागर में 'आदर्श क्रीडा मंडल' टीम की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने गया था। गांव की कुछ अन्य टीमों ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि वह स्थानीय निवासी



नहीं है और 'बाहरी' है। अधिकारी ने बताया कि रविवार तड़के जब खोत अपने घर के बाहर रिश्तेदारों के साथ बैठे थे, तभी ओमकार बोरकर, अविनाश शेठेय और साईप्रसाद बोरकर ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि तीनों ने गाली-गलौज करते हुए लोहे की छड़ से मारपीट की और घुंसे भी मारे। खोत के जमीन पर गिरने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

आरोपियों को 20 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत

खोत के रिश्तेदारों की शिकायत पर गुहागर पुलिस थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने अदालत में अधिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 20 फरवरी तक रोक लगा दी है। इस बीच, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में खोत की बुजुर्ग मां ने बुधवार को गुहागर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया और न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही।

स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से तेज़ होगा महाराष्ट्र का विकास : मुख्यमंत्री

टाटा ट्रस्ट और नाम फाउंडेशन के साथ योजनाओं पर हुई उच्चस्तरीय बैठक

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र की प्रगति को गति देने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs) की भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने विश्वास जताया कि टाटा ट्रस्ट और नाम फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने से राज्य में न केवल तेजी से बदलाव आएगा, बल्कि विकास की निरंतरता भी बनी रहेगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार और इन संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित कर जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना था। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हर परिवार को बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित पेयजल और आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। उन्होंने विशेष रूप से गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज से आम जनता को होने वाली परेशानी का जिक्र किया।



बैठक में उपस्थित प्रमुख हस्तियाँ

इस उच्च स्तरीय बैठक में शासन और सामाजिक क्षेत्र के कई दिग्गज शामिल हुए। इनमें मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉ. निपुण विनायक और अनूप कुमार यादव उपस्थित थे। इसके अलावा टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा और नाम फाउंडेशन के प्रमुख पदाधिकारी भी चर्चा का हिस्सा बने। यह बैठक इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र सरकार आगामी समय में सामाजिक संगठनों के सहयोग से विकास के एक नए 'पीपीपी' (Public-Private-Partnership) मॉडल को बढ़े पैमाने पर लागू करने जा रही है।

जल संरक्षण और 'जलयुक्त शिवार' की सफलता

जल सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने 'नाम फाउंडेशन' के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नदियों और नालों को गहरा करने तथा गाढ़ निकालने के कार्यों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। राज्य की 'जलयुक्त शिवार' योजना, जो अब एक जन आंदोलन बन चुकी है, को नाम फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के तकनीकी व आर्थिक सहयोग से काफी मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने इसे एक सफल मॉडल बताया जो सीधे तौर पर किसानों के जीवन से जुड़ा है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने महाराष्ट्र सरकार के साथ अपनी साझेदारी को और अधिक सशक्त करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाकर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।

29 श्रम कानूनों की बहाली हेतु राष्ट्रव्यापी हड़ताल

सड़क पर काम करने वालों, प्रोफेसरों, मंत्रालय के कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल का किया समर्थन

मुंबई। केंद्र सरकार द्वारा दशकों के संघर्ष के बाद प्राप्त 29 श्रम कानूनों को रद्द कर चार नए 'लेबर कोड' लागू करने के निर्णय के खिलाफ देश भर के श्रमिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। लेबर यूनियनों का तर्क है कि ये नए कोड मजदूरों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और इन्हें बिना किसी चर्चा के थोपा गया है। इसी विरोध स्वरूप 12 फरवरी को आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मुंबई में व्यापक असर देखने को मिला, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों ने एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ पुरजोर प्रदर्शन किया।

प्रमुख मांगों और भविष्य की रणनीति श्रमिकों की मुख्य मांगों में 4 नए लेबर कोड को तत्काल समाप्त करने, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये निर्धारित करने और निजीकरण पर रोक लगाने जैसी बातें शामिल हैं। इसके अलावा, आशा वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देने, उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, किसानों की कर्ज माफ़ी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की भी मांग की गई है।

मुंबई में एकजुटता और बीकेसी में विशाल प्रदर्शन



इस आंदोलन को मुंबई के रेहड़ी-पटरी वालों, निर्माण श्रमिकों, प्रोफेसरों, बैंक कर्मचारियों और मंत्रालय के कर्मचारियों का भरपूर समर्थन मिला। 'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन' (CITU), INTUC और अन्य प्रमुख संगठनों के नेतृत्व में आजाद मैदान और बीकेसी स्थित लेबर कमिश्नर हाउस पर करीब 5,000 मजदूरों ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। सुबह से शाम तक चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान संयुक्त कृति समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने लेबर कमिश्नर से मुलाकात कर अपनी मांगों का मेमोरेंडम सौंपा। डॉ. विवेक मोटेरो, एमएलए सचिन अहीर और अन्य प्रमुख श्रमिक नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व कर श्रमिकों की आवाज को बुलंद किया।

अजित दादा के अधूरे सपनों को पूरा करना हमारा दायित्व: सुले

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने गुरुवार को कहा कि 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में निधन हुए अजित पवार के अधूरे सपनों को पूरा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है और सभी सदस्य एक-दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में सुप्रिया सुले ने कहा कि 'दादा (अजित पवार) अब हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए मैं पुराने मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। हमारे बीच जो भी चर्चाएं हुई थीं, वे हमारे बीच ही रहेंगी। अब हमारा कर्तव्य है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करें।'

नेताओं का जताया आभार, बेटी की शादी पर बयान



सुप्रिया सुले ने यह भी बताया कि जब शरद पवार अस्पताल में भर्ती थे, तब विभिन्न दलों के नेताओं ने फोन कर हालवाला पूछा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राजलु गांधी, रक्षा मंत्री जयनाथ सिंह और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित सभी नेताओं का जनवाद किया। अपनी बेटी रेवती की संरक्षण लखानी से शादी की घोषणा पर सुले ने कहा कि दोनों एक साल से एक-दूसरे को जानते हैं और इस रिश्ते पर कई महीनों से बातचीत चल रही थी। उन्होंने बताया कि शादी का फैसला अजित पवार के जीवित रहते ही हो गया था और उनके आशीर्वाद से यह रिश्ता तय हुआ।

दाढ़ी और टोपी के कारण मुसलमानों के साथ हो रहा भेदभाव: अबू आजमी

मुंबई! समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक अबू आजमी ने एक बार फिर अपने बेबाक बयानों से देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए आजमी ने केंद्र सरकार और मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2014 के बाद से देश का माहौल इस कदर बदला है कि आज भारत का मुसलमान खुद को 100 प्रतिशत सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आजमी ने आरोप लगाया कि सत्ता में बने रहने के लिए धार्मिक पहचान जैसे दाढ़ी और टोपी को निशाना बनाकर नफरत का राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बीएमसी की पूर्व मेयर रितु तावड़े के 'बांग्लादेशी घुसपैठियों' वाले बयान पर पलटवार करते हुए आजमी ने मुसलमानों की वफादारी का बचाव किया। उन्होंने गवर्नर से याद दिलाया कि 'साठे कर्हों से अच्छा' का नारा एक मुसलमान ने ही दिया था और आजादी से लेकर सरहद की सुरक्षा तक मुसलमानों ने हमेशा अपनी जान कुर्बान की है।

पूर्व राज्यपाल कोश्यारी पर ठाकरे गुट और मनसे का पलटवार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस बयान के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मनसे प्रमुख राज ठाकरे डरते हैं। इस टिप्पणी पर शिवसेना (ठाकरे गुट) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।



मनसे की तीखी प्रतिक्रिया

मनसे नेता संदीप देशपांडे ने भी कोश्यारी के बयान पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यदि आज भगत सिंह जीवित होते तो कोश्यारी को सबक सिखाते। देशपांडे ने यह भी कहा कि कोश्यारी को अपने नाम से "भगत सिंह" शब्द हटा देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कोश्यारी

ने बुधवार को नासिक में एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी के मुद्दे पर बोलते हुए राज ठाकरे की आलोचना की थी, जिसके बाद यह विवाद खड़ा हुआ है। कोश्यारी के बयान ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज कर दिया है।

'हमें समझदारी न सिखाएं'

शिवसेना (ठाकरे गुट) के सांसद संजय राऊत ने कोश्यारी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उन्हें समझदारी न सिखाएं। राऊत ने तंज कसते हुए कहा कि "जो लोग ठीक से धोती नहीं पहन सकते, वे हमें कॉमन सेंस सिखा रहे हैं।" उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी से कौन डरता है? राऊत ने कहा कि लोकसभा में जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सदन छोड़कर चले गए। राऊत ने यह भी आरोप लगाया कि कोश्यारी ने पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा फुले का अपमान किया है।

एनसीपी विलय की चर्चा पर क्या बोलीं?

एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि परिवार अभी शोक में है, इसलिए इस समय ऐसे विषयों पर चर्चा करना ठीक नहीं है।

अजित पवार की योजनाओं का जिक्र

सुप्रिया सुले ने बताया कि अजित पवार के कार्यकाल में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि और कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर हुई थी। उन्होंने पुणे की सफल 'कृषक' पहल का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह अजित पवार का सपना था और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

किसानों और व्यापार समझौते पर सवाल

किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर किसानों को फायदा हो तो सभी खुश होंगे, लेकिन किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते से भारत को क्या लाभ

होगा, यह सरकार को साफ-साफ बताना चाहिए। उन्होंने केंद्र द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दिए जा रहे जोर का भी उल्लेख किया।

विमान हादसे पर जांच की मांग

वहीं एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार की तरफ से उठाई गई शंकाओं पर सुले ने कहा कि उनकी चिंता स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे की विस्तृत जांच का भरोसा दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि 'कई सवाल हैं- क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इसे रोका जा सकता था, इन सबका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए।'

मुंबई के कचरे से बनेगी बिजली

कांजूरमार्ग और देवनार में 'वेस्ट टू एनर्जी' परियोजनाओं को गति देने के निर्देश

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने मुंबई में प्रतिदिन इकट्ठा होने वाले कचरे से बिजली उत्पादन की महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को 'वेस्ट टू एनर्जी' परियोजना में आ रही अड़चनों को दूर कर काम तेज करने को कहा है।



समीक्षा बैठक में दिए स्पष्ट निर्देश

मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि सरकार इस अभिनव परियोजना को स्वीकृति देने के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन में आने वाली सभी बाधाओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बीएमसी का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा। कांजूरमार्ग स्थित 'वेस्ट टू एनर्जी' परियोजना से लगभग 8,000 मेगावाट विद्युत

उत्पादन क्षमता विकसित करने की योजना है। इसके अलावा देवनार में 500 मेगावाट क्षमता की एक अन्य परियोजना स्थापित की जा रही है। मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा और उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इससे एक ओर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा।

स्थानीय निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की उद्भव ठाकरे ने सराहना की

मुंबई। शिवसेना (उद्भव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्भव ठाकरे ने महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारी धनबल के बावजूद निष्ठा की दीवार को भेदा नहीं जा सका। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा, "आपने शानदार काम किया है। आपने मुश्किल समय में सफलता हासिल की है। धन-बल का बोलबाला था, लेकिन निष्ठा की दीवार को वह तोड़ नहीं सका। कल हमारा होगा।" भाजपा के नेतृत्व वाले 'महायुति' गठबंधन ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में उल्लेखनीय जीत दर्ज की है। इन चुनावों के नतीजे सोमवार को घोषित किए गए। 731 जिला परिषद सीटों में से महायुति ने 552 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं 1462 पंचायत समिति सीटों में से 1000 से अधिक सीटें गठबंधन के खाते में गईं। जिला परिषद चुनाव में भाजपा 225 सीटों के साथ सबसे आगे रही। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (165 सीट) और शिवसेना (162 सीट) का स्थान रहा। इन परिणामों के साथ महायुति ने 2024 के विधानसभा चुनावों में अपने मजबूत प्रदर्शन के बाद जीत का सिलसिला जारी रखा है।



तिलक ब्रिज पर भारी वाहनों की एंट्री तीन माह बंद

12 मई तक सुबह 7 से रात 11 बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महानगर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच दादर स्थित तिलक ब्रिज पर 12 मई 2026 तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के आदेशानुसार सुबह 7 बजे से रात 11 बजे के बीच ट्रैवल, मिक्सर, डंपर, ट्रेलर सहित अन्य भारी वाहनों को इस पुल से गुजरने की अनुमति नहीं होगी।

ईस्टर्न सबर्स और नवी मुंबई से आने वाले भारी वाहन सायन हॉस्पिटल जंक्शन से दाएं मुड़कर सुलोचना शेड्डी मार्ग, कुंभारवाड़ा जंक्शन, कटारिया मार्ग, सावरकर रोड, वैद्यभूमि, सिद्धिविनायक मंदिर और अप्पासाहेब मराठे चौक होते हुए अपने गंतव्य तक

सायन और एलफिंस्टन ब्रिज कार्य के कारण निर्णय



सायन रेलवे ब्रिज और एलफिंस्टन प्लाईओवर के पुनर्निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। ठाणे और नवी मुंबई से आने वाले वाहनों को धारावी और तिलक ब्रिज की ओर डायवर्ट

किए जाने से दादर और माटुंगा क्षेत्र में भारी जाम की स्थिति बन रही थी। इमरजेंसी वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

वैकल्पिक मार्ग तय

जाएंगे। परेल और लालबाग की दिशा में जाने वाले वाहन दादर टीटी ब्रॉडवे जंक्शन से हिंदमाता ब्रिज, परेल वर्कशॉप, लालबाग ब्रिज के नीचे, भारतमाता सिग्नल और चिंचोपकली ब्रिज मार्ग का उपयोग करेंगे। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड से उत्तर दिशा

में जाने वाले भारी वाहन तिलक ब्रिज के बजाय दादर टीटी सर्कल, माहेश्वरी सर्कल, अरोड़ा जंक्शन, सायन हॉस्पिटल, कुंभारवाड़ा जंक्शन, कटारिया ब्रिज, सावरकर रोड और सिद्धिविनायक मंदिर मार्ग से गुजरेंगे।

कोल्हापुर में होगी 'मंदिर क्रिकेट लीग'

मुंबई/कोल्हापुर। कोल्हापुर में मंदिर क्रिकेट लीग का आयोजन होना जा रहा है। इस लीग में मंदिरों को पुजारी शामिल होंगे और अपने हुनर को क्रिकेट के मैदान पर दिखाएंगे। मंदिर क्रिकेट लीग का आयोजन 14 से 16 फरवरी तक किया जाएगा। इसमें राज्य के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के पुजारी शामिल होंगे। इतना ही नहीं इसके लिए मंदिर के पुजारी तैयारी भी कर रहे हैं, उनमें उत्साह भी देखा जा रहा है, साथ ही क्रिकेट की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, मंदिर क्रिकेट लीग में राज्य के कई मंदिरों को पुजारी शामिल होंगे। इनमें अंबाबाई मंदिर, शिरडी के साईबाबा मंदिर, तुलजापुर, पंढरपुर, माहुरगढ़, नरसिंह वाडी, कोल्हापुर के ज्योतिबा मंदिर के पुजारी भाग लेंगे। वहीं मंदिर के पुजारियों और अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ मैदान में उतरकर जमकर अभ्यास किया, जो मैदान में प्रैक्टिस भी करते नजर आ रहे हैं।



मध्य रेल

सुली निविदा सूचना
सुली ई-निविदा संस्था:
केवाएनएलसी-585-डब्ल्यू-746-कांस्ट-आर2
कार्य का विवरण: मध्य रेल के मुंबई मंडल के कल्याण जिले में वांगी, तामझाल और इलापुरी टीएएसए और वांगी, आसनगांव, कसाव, कर्जत एलएएसई में 110 केवी स्विचघराई में पुरानी फिटिंग और आसबीलेटर्स का प्रतिस्थापन। अनुमानित लागत: ₹6,16,25,940.92, ईएमडी: ₹4,58,100/-
निविदा पत्र का शुल्क: 0.00, समापन अवधि: 12 महीने। ई-निविदा चक्र करने की अंतिम तिथि एवं अवधि दि. 05.03.2026 को 11:00 बजे है। ई-निविदा की विस्तृत जानकारी रेल की अधिकारीक वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा की जानकारी वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि) मध्य रेल कल्याण के सुचना पट पर उपलब्ध है। सुरक्षित याना करें, फुटवॉर्ड पर यात्रा न करें

संपादकीय

एक हरित क्रांति की दस्तक

मुंबई जैसे महानगर के लिए कचरा प्रबंधन हमेशा से एक विकराल चुनौती रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र की पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे द्वारा बीएमसी को 'वेस्ट टू एनर्जी' (कचरे से बिजली उत्पादन) परियोजनाओं को शीघ्र लागू करने के निर्देश देना, इस दिशा में एक युगांतकारी कदम साबित हो सकता है। कांजूरमार्ग और देवनार में प्रस्तावित ये परियोजनाएं न केवल कचरे के पहाड़ों से मुक्ति दिलाएंगी, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भी मुंबई को आत्मनिर्भर बनाएंगी। मंत्री महोदया का यह निर्देश कि इन परियोजनाओं में आ रही सभी बाधाओं का समाधान निकाला जाए, प्रशासन की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है। मुंबई प्रतिदिन लगभग 6,000 से 7,000 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न करती है। अब तक इस कचरे का बड़ा हिस्सा देवनार और कांजूरमार्ग जैसे डंपिंग ग्राउंड्स में केवल डंप किया जाता रहा है, जिससे न केवल भूमि प्रदूषित होती है, बल्कि मीथेन जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। 'वेस्ट टू एनर्जी' तकनीक इस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से उपचारित कर बिजली पैदा करती है। कांजूरमार्ग स्थित परियोजना से लगभग 8,000 मेगावाट और देवनार से 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता विकसित करना न केवल कचरा निस्तारण का समाधान है, बल्कि मुंबई के बिजली ग्रिड को मजबूती प्रदान करने का एक अभिनव प्रयास भी है। वैश्विक स्तर पर देखें तो कचरे को ऊर्जा में बदलना एक अत्यंत सफल और अनिवार्य मॉडल बन चुका है। स्वीडन जैसे विकसित देश अपने कुल कचरे का 99% हिस्सा रिसाइकिल या ऊर्जा उत्पादन में उपयोग करते हैं। स्थिति यह है कि स्वीडन को अपने संयंत्र चलाने के लिए अब दूसरे देशों से कचरा आयात करना पड़ता है। इसी प्रकार, सिंगापुर ने अपनी सीमित भूमि के बावजूद अत्याधुनिक तकनीक से कचरे को बिजली में बदलकर मिसाल पेश की है। चीन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा 'वेस्ट टू एनर्जी' उत्पादक है। यदि ये देश कचरे को राष्ट्रीय संपदा में बदल सकते हैं, तो मुंबई के पास संसाधनों और कचरे की कोई कमी नहीं है। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के इस दौर में मुंबई के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुंबई के लिए इस परियोजना के लाभ केवल बिजली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव भी व्यापक होंगे। डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाली आबादी दशकों से सांस की बीमारियों और दुर्गंध से जूझ रही है; वैज्ञानिक निस्तारण उन्हें एक स्वस्थ जीवन प्रदान करेगा। साथ ही, डंपिंग ग्राउंड के रूप में फंसी हुई करोड़ों की कीमती जमीन मुक्त होगी, जिसका उपयोग पार्कों या जनोपयोगी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। मंत्री पंकजा मुंडे का यह आश्वासन कि सुप्रीम कोर्ट में बीएमसी का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा, इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार कानूनी पेचीदगियों को विकास के आड़े नहीं आने देगी। अंततः, यदि मुंबई इस 'संकुलर इकोनॉमी' मॉडल को सफलतापूर्वक अपना लेती है।

शख्सियत

सरोजिनी नायडू

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 'भारत कोकिला'



सरोजिनी नायडू भारतीय इतिहास की उन महान महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने न केवल राजनीति बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।

उन्हें 'भारत कोकिला' (The Nightingale of India) के नाम से जाना जाता है। उनका व्यक्तित्व साहस, विद्वता और संवेदनशीलता का एक अद्भुत संगम था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी, 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता, अधोपनाथ चट्टोपाध्याय, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद् थे, और उनकी माँ, वरद सुंदरी, एक कवयित्री थीं। बचपन से ही सरोजिनी अत्यंत मेधावी थीं। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, जिसने उनकी बौद्धिक क्षमता का लोहा मनवाया। उनकी साहित्यिक प्रतिभा को देखते हुए, हैदराबाद के निजांम ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड भेजा। वहाँ उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही उन्हें प्रसिद्ध अंग्रेजी आलोचकों से मिलने और अपनी काव्य प्रतिभा को निखारने का अवसर मिला। साहित्यिकयोगदान सरोजिनी नायडू एक उच्च कोटि की कवयित्री थीं। उनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति, प्रकृति और लोक जीवन की सुंदरता का जीवंत चित्रण मिलता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में शामिल हैं: 'द गोल्डन ब्रेडोल्ड * द बर्ड ऑफ टाइम (The Bird of Time) द ब्रोकन विंग (The Broken Wing) उनकी कविताओं की लय

और मिठास के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें 'भारत कोकिला' की उपाधि दी थी। उनकी कविताओं में देशभक्ति और मानवीय भावनाओं का गहरा समावेश था। स्वतंत्रता संग्राम में भीमिका 1905 में बंगाल विभाजन के समय सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुईं। उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले, रवींद्रनाथ टैगोर और एनी बेसेंट जैसे दिग्गजों से हुई। 1916 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी शक्ति देश की आजादी के लिए झोंक दी। वे एक प्रखर वक्ता थीं और उन्होंने देश-विदेश में घूमकर भारतीयों को स्वराज्य के प्रति जागरूक किया। 1925 में कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गईं। उन्होंने 'नमक सत्याग्रह' और 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गईं। महिला सशक्तिकरण की अग्रदूत नायडू ने न केवल लड़कियों का आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा के लिए भी निरंतर आवाज उठाई। उन्होंने 'विमेन इंडिया एसोसिएशन' (WIA) की स्थापना में मदद की और मताधिकार के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। उनका मानना था कि जब तक महिलाएँ शिक्षित और जागरूक नहीं होंगी।

पुनर्निर्माण से पुनरुत्थान तक की कठिन राह

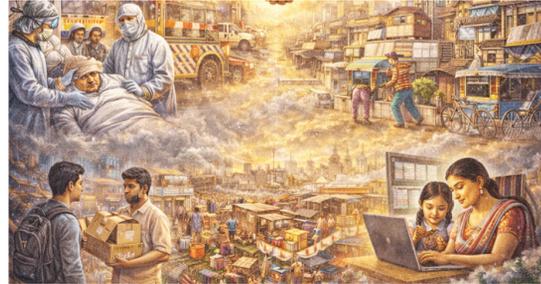


धीरज सिंह समाचार संपादक

जलवायु परिवर्तन और बाढ़ जैसी आपदाएं भी महानगरों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं। इसके साथ ही, प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को मजबूत करना भी आवश्यक है। कोविड काल में लोगों ने सूचना और सहयोग की अहमियत समझी। अब नागरिक अपेक्षा करते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो। मेयर को डिजिटल प्लेटफॉर्म, जनसुनवाई और सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से भरोसा कायम करना होगा।

कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर के शहरों की संरचना, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को गहराई से प्रभावित किया। मुंबई सहित देश के बड़े महानगरों ने इस संकट का सबसे अधिक बोझ उठाया। अब जब नए मेयर अपने दायित्व संभाल रहे हैं, तो उनके सामने केवल नियमित शहरी प्रशासन की जिम्मेदारियाँ नहीं, बल्कि महामारी के बाद के पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान की जटिल चुनौती भी है। यह समय केवल प्रबंधन का नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और संवेदनशील नेतृत्व का है। सबसे बड़ी चुनौती सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की है। कोविड ने स्पष्ट कर दिया कि महानगरों की स्वास्थ्य प्रणाली अत्यधिक दबाव में है। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन संकट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सीमित क्षमता—ये सब अनुभव अभी भी ताजा हैं। नए मेयर को यह सुनिश्चित करना होगा कि शहरी स्वास्थ्य ढांचा केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी मजबूत और सुलभ हो। अस्पतालों पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, और महामारी निगरानी तंत्र की स्थापना अब अनिवार्य हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती आर्थिक पुनरुद्धार की है। कोविड के दौरान लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गईं, छोटे व्यापार बंद हुए और अनौपचारिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। मुंबई जैसे शहर की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र, फिल्म उद्योग, पर्यटन, रियल एस्टेट और छोटे कारोबारों पर आधारित

है। नए मेयरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की पहल करनी होगी, स्टार्टअप और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा, तथा बाजारों को फिर से सक्रिय बनाने के लिए टोस कदम उठाने होंगे। नगर निगमों की नीतियाँ यदि स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दें, तो शहर की आर्थिक धड़कन फिर से तेज हो सकती है।



तीसरी चुनौती वित्तीय संसाधनों की कमी है। महामारी के दौरान नगर निगमों का राजस्व घटा, जबकि स्वास्थ्य और राहत कार्यों पर खर्च बढ़ा। संपत्ति कर और अन्य आय स्रोतों में गिरावट आई। ऐसे में नए मेयर को सीमित संसाधनों में प्राथमिकताएँ तय करनी होंगी। पारदर्शी बजट प्रबंधन, कर संग्रह की दक्षता बढ़ाना, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से परियोजनाओं को आगे बढ़ाना उनकी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। वित्तीय अनुशासन और नवाचार दोनों की आवश्यकता होगी। चौथी चुनौती सामाजिक असमानता को कम करने की है। कोविड ने यह उजागर किया

कि शहरों में अमीर और गरीब के बीच खाई कितनी गहरी है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए—न तो पर्याप्त स्थान, न स्वच्छता की सुविधा, न स्वास्थ्य सेवाओं की सहज पहुँच। नए मेयर को समावेशी शहरी विकास की दिशा में टोस कदम उठाने होंगे। सस्ती आवास योजनाएँ, स्वच्छ पानी, बेहतर स्वच्छता

और डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करना अब विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता है। शिक्षा भी एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ महामारी का गहरा असर पड़ा। ऑनलाइन शिक्षा ने डिजिटल विभाजन को उजागर किया। नगर निगम स्कूलों के छात्रों को पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाए। नए मेयर को यह सुनिश्चित करना होगा कि शहरी शिक्षा व्यवस्था तकनीकी रूप से सक्षम बने, और गरीब परिवारों के बच्चों को भी समान अवसर मिलें। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। पर्यावरण और शहरी नियोजन भी नई

चुनौतियाँ लेकर सामने आए हैं। महामारी के दौरान साफ हवा और कम प्रदूषण ने यह संकेत दिया कि शहरों को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही गतिविधियाँ सामान्य हुईं, प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या फिर उभर आई। नए मेयर को हरित परिवहन, साइकिल ट्रैक, सार्वजनिक परिवहन के विस्तार और खुले स्थानों के संरक्षण पर ध्यान देना होगा। जलवायु परिवर्तन और बाढ़ जैसी आपदाएँ भी महानगरों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं। इसके साथ ही, प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को मजबूत करना भी आवश्यक है। कोविड काल में लोगों ने सूचना और सहयोग की अहमियत समझी। अब नागरिक अपेक्षा करते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो। मेयर को डिजिटल प्लेटफॉर्म, जनसुनवाई और सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से भरोसा कायम करना होगा। अंततः, कोविड के बाद का दौर केवल चुनौतियों का नहीं, बल्कि अवसरों का भी है। यह समय शहरों को अधिक मानवीय, समावेशी और टिकाऊ बनाने का है। नए मेयर यदि दूरदृष्टि, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ काम करें, तो वे इस संकट को परिवर्तन के अवसर में बदल सकते हैं। महामारी ने हमें सिखाया कि शहर केवल इमारतों का समूह नहीं, बल्कि लोगों का जीवंत समुदाय हैं। इन समुदायों को सुरक्षित, सशक्त और आशावान बनाना ही नए मेयरों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और परीक्षा होगी।

हमारी गीता



स्वामिनी निष्कलानंदा चिन्मय मिशन कल्याण

श्रीमद्भगवद्गीता का प्रथम श्लोक केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन के सूक्ष्म विश्लेषण का आधार है। जिस प्रकार एक चिकित्सक किसी बीमारी का इलाज करने से पहले टेस्ट के माध्यम से रोग की जड़ को पहचानता है, गीता भी हमारे जीवन के विकारों के लिए वैसी ही सटीक औषधि है। धृतराष्ट्र का अपने और पांडवों के पुत्रों के विषय में पूछा गया प्रश्न हमें अहंकार और शूद्र चेतना के बीच के अंतर को समझाता है। धृतराष्ट्र की वृत्ति उस 'ममत्व' का प्रतीक है जो 'यह मेरा-यह मेरा' के मोह में फंसी है, जबकि पांडव उस शूद्र और पित्र



हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे प्राप्त करना ही मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है। लेख में 'समवेता' शब्द का अर्थ अत्यंत गूढ़ है, जो यह दर्शाता है कि धर्म और अधर्म की ये वृत्तियाँ एक ही वंश की हैं—अर्थात्

अंतर्मन का निदान और वृत्तियों का द्वंद्व

हमारे एक ही मन का हिस्सा है। हमारा मन ही वह रणभूमि है जहाँ कभी लोभ और क्रोध जैसे कौरव जन्म लेते हैं, तो कभी संतोष और शांति जैसे पांडव। एक ही मन में कामनाओं का जाल भी बुनता है और वहीं ब्रह्मचर्य की ओर भी प्रेरित होता है। धृतराष्ट्र द्वारा युद्ध के दसवें दिन पूछा गया प्रश्न 'किम् अकूतम्' (क्या किया) केवल बाहरी क्रिया जानने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक गहरी जिज्ञासा थी कि क्या 'धर्मक्षेत्र' के प्रभाव से दुर्बोधन की अधर्म बुद्धि में कोई सकारात्मक बदलाव आया। अंततः, हमें 'धर्मक्षेत्र' को मंदिर, मस्जिद

या पूजा-पाठ के संकुचित ढांचे से बाहर निकलकर देखना होगा। वास्तविकता में, यह 'शरीर' ही वह साधन और क्षेत्र है जहाँ हमारे सभी कर्म घटित होते हैं। धर्म केवल यज्ञशालाओं में नहीं रहता, बल्कि वह हमारे दैनिक कर्मों के बीच में निवास करता है। इसीलिए भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का महान उपदेश किसी शांत गुफा में नहीं, बल्कि जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण रणभूमि के बीच दिया। यह स्पष्ट करता है कि जब हम अपने संघर्षमय कर्मक्षेत्र को ही धर्मक्षेत्र समझकर कार्य करते हैं, तभी जीवन में वास्तविक रूपांतरण संभव है।

जीवन ऊर्जा

13 अगस्त, 1926 में जन्मे कास्त्रो क्यूबा के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने 1959 की क्रांति के माध्यम से क्यूबा में तानाशाही शासन को उखाड़ फेंका और वहाँ कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की।

क्रांति भविष्य और अतीत के बीच का संघर्ष है

इतिहास मुझे दोषमुक्त कर देगा। क्रांति गुलाबों का विस्तर नहीं है। क्रांति भविष्य और अतीत के बीच का संघर्ष है। मैं तब तक आराम नहीं करूँगा जब तक कि साम्राज्यवाद का पूरी तरह से अंत न हो जाए। एक क्रांतिकारी कभी भी बूढ़ा नहीं होता, वह केवल परिपक्व होता है। सिद्धांतों के लिए मरना कहीं बेहतर है, बजाय उन सिद्धांतों के बिना जीने के। क्रांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप चुनते हैं, यह वह है जो आपको चुनती है। हथियार केवल बचाव के लिए होते हैं, क्रांति तो विचारों से आती है। पूंजीवाद घृणित है। यह केवल लालच और युद्ध लाता है। मैं एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी हूँ और अपने जीवन



के अंतिम दिन तक यही रहूँगा। अमेरिकी साम्राज्य की असली ताकत उनकी सेना नहीं, बल्कि उनके द्वारा फैलाया गया झूठ

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

प्रेम और ईश्वर: एक ही सिक्के के दो पहलू

अध्यात्म की गहराइयों में जब हम उतरते हैं, तो दो शब्द सबसे अधिक गुंजते हैं—'प्रेम' और 'ईश्वर'। संसार के लगभग सभी धर्मों, संतों और दार्शनिकों ने अंततः इसी निष्कर्ष पर अपनी मुहर लगाई है कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। लेकिन यह प्रेम वह नहीं है जिसे हम सांसारिक मोह-माया या आकर्षण के रूप में जानते हैं; यह वह अलौकिक 'अनासक्त प्रेम' है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। साधारण अर्थ में हम प्रेम को एक भावना मानते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या संबंध

तक सीमित होती है। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम एक 'अवस्था' (State of Being) है। प्रेम का अर्थ है—स्वयं को मिटाकर दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना। सूफी संत रूमी कहते थे, रप्रेम



वह पुल है जो आपको और सब कुछ को जोड़ता है। जब हृदय में निश्चय प्रेम का उदय होता है, तो 'मैं' (अहंकार) विलीन होने लगता है। जहाँ 'मैं' समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर की यात्रा शुरू होती है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो बादलों के पार बैठा न्याय कर रहा है। ईश्वर वह चेतना है जो ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है। उपनिषदों में कहा गया है—ईश्यावस्यमिदं सर्वम् अर्थात् यह

सब कुछ ईश्वर से ही व्याप्त है। जब हम प्रेमपूर्ण होते हैं, तो हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है और हमें उसी ईश्वर का दर्शन हर जीव में होने लगता है। कबीर दास जी ने ठीक ही कहा था—रूपोथी पढ़ि-

समाप्त हो जाता है। जब भक्त कहता है 'रमै तेरा हूँ, र तो वह प्रेम है। लेकिन जब वह इस परकाष्ठा पर पहुँचता है कि रत्न ही तू है, र तो वह साक्षात् ईश्वरानुभूति है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि जो प्रेम हम बाहर खोज रहे हैं, वह हमारे भीतर ही है। ईश्वर हमारे हृदय में 'आत्मा' के रूप में विराजमान है। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ अहंकार पालना नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति का सम्मान करना है। जब हम स्वयं को प्रेम करते हैं, तो हम शांत और आनंदित होते हैं। एक आनंदित व्यक्ति ही संसार को प्रेम दे सकता है। जिसे स्वयं में ईश्वर नहीं दिखा, उसे मंदिर या मस्जिद में भी वह कभी नहीं मिलेगा। सांसारिक प्रेम अक्सर अपेक्षाओं (Expectations) की जंजीरों में बंधा होता है, इसलिए वह दुख का कारण बनता है। इसके विपरीत, आध्यात्मिक प्रेम 'अनासक्त' होता है। यह सूरज की रोशनी की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाशित करती है। जब हमारा प्रेम केवल परिवार या मित्रों तक सीमित न रहकर संपूर्ण सृष्टि (पशु-पक्षी, प्रकृति, शत्रु और मित्र) के लिए एक समान हो जाता है, तो समझ लीजिए कि हमने ईश्वर के द्वार पर दस्तक दे दी है। प्रेम और ईश्वर अलग-अलग नहीं हैं।



पंडित कैलाशचंद्र शर्मा वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक। मो. नं. 9425980556

अपने विचार

ये पूरी तरह से तानाशाही है। सरकार इसके जरिए अत्याचार कर रही है। आखिर कहाँ लिखा है कि 'वंदे मातरम्' संविधान का हिस्सा है? यह न तो संविधान का हिस्सा है और न ही राष्ट्रगान है। राष्ट्रगानों का सम्मान हर कोई करता है। जहाँ तक 'वंदे मातरम्' की बात है, तो यह इस्लाम के एफेश्वरवाद के विरुद्ध और धार्मिक नैतिकता के खिलाफ है।

'स्टूडेंट्स हैं आक्रोश में आकर ऐसा कह देते हैं, उसका कोई अक्षरशः मतलब थोड़ी न होता है। तमाम ऐसी जगहों पर नारे लगते हैं देश के गद्दारों को मारो जूते चार, तो ये आम बातें हैं। इसका मतलब ये थोड़ी न है कि जिसके खिलाफ नारे लगते हैं उन्हें वास्तव में जूता मारा जाता है।

इस तरह के आंदोलनों की वजह से पहले ही केरल की काफी बदनामी हो चुकी है। इस उग्र यूनिफनवाद, जिसे दुनिया के बाकी देशों यहाँ तक की भारत के बाकी राज्यों ने भी त्याग दिया है, लेकिन केरल लगातार इसे अपनाए हुए है। इसकी वजह से उद्योग धंधे भी राज्य से दूर हो रहे हैं।

'राहुल गांधी जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं और मर्यादा छोड़कर सिर्फ सदन में बोलने के लिए बातों को बोलना में मानता हूँ वो गंभीर पद पर हैं और उन्हें अपनी पद की गंभीरता को समझना जरूरी है। विशेषाधिकार प्रस्ताव एक अधिकार है।

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय

ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

ब्रीफ न्यूज़

उल्हासनगर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और बढ़ते प्रदूषण पर मनसे का अल्टीमेटम



उल्हासनगर। उल्हासनगर में एमएमआरडीए द्वारा कल्याण-बदलापुर राज्य महामार्ग के निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं और उससे फैलने वाले प्रदूषण को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने कड़ा रुख अपनाया है। मनसे शहर प्रमुख बंडू देशमुख ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि 65 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस सड़क का कार्य अत्यंत घटिया दर्जे का है, जिसमें पुरानी सड़क के ऊपर ही नई परत चढ़ाकर उसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, जिससे मानसून में स्थानीय दुकानों में पानी घुसने का खतरा पैदा हो गया है। सड़क पर अभी से दरारें (क्रैक्स) पड़ने और भारी धूल से जनजीवन प्रभावित होने के कारण मनसे ने इस पूरे प्रोजेक्ट को आईआईटी मुंबई या किसी 'थर्ड पार्टी' से जांच कराने की मांग की है। बंडू देशमुख ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 16 फरवरी तक ठेकेदार पर कार्रवाई और प्रदूषण नियंत्रण के ठोस उपाय नहीं किए गए, तो मनसे कार्यकर्ता संबंधित कार्यालयों में रमनसे स्ट्राइक में उग्र आंदोलन करेंगे।

नायागांव स्टेशन का उत्तरी फुट ओवर ब्रिज 14 फरवरी से रहेगा बंद

मुंबई। नायागांव स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज तथा प्लेटफॉर्म के निर्माण/विस्तार कार्य के संबंध में प्लेटफॉर्म संख्या 1 को प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3 से जोड़ने वाला मौजूदा उत्तरी फुट ओवर ब्रिज 14 फरवरी, 2026 से डेढ़ महीने के लिए यात्रियों के उपयोग हेतु बंद रहेगा। इस अवधि के दौरान यात्री नायागांव स्टेशन पर उपलब्ध अन्य तीन फुट ओवर ब्रिज तथा सबवे का उपयोग कर सकते हैं।

न्यू कस्टम हाउस में सीबीआईसी का पोस्ट-बजट संवाद सत्र आयोजित

व्यापार एवं उद्योग प्रतिनिधियों के साथ हुई व्यापक चर्चा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने मुंबई स्थित न्यू कस्टम हाउस में व्यापार संघों, चैंबर ऑफ कॉमर्स, निर्यातकों, आयातकों, कस्टोडियंस, कस्टम ब्रोकर्स, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ पोस्ट-बजट संवाद सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी और सदस्य (आईटी, करदाता सेवाएं एवं प्रौद्योगिकी) योगेंद्र गर्ग ने की। इस अवसर पर मुंबई कस्टम और जीएसटी के प्रधान मुख्य आयुक्त, संयुक्त सचिव (कस्टम), आयुक्त (कस्टम एवं निर्यात संवर्धन), आयुक्त जीएसटी नीति प्रकोष्ठ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर

संवाद सत्र के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी अध्यक्ष ने मुंबई कस्टम, एयरपोर्ट, कूरियर टर्मिनल और सीजीएसटी में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर सुधारात्मक पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापार एवं उद्योग के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया।

भरोसा-आधारित प्रशासन और नई सुधार पहलें

सीबीआईसी अध्यक्ष ने केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़े सुधारों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये पहलें 'ट्रस्ट-वेड्ड गवर्नेंस' यानी भरोसा-आधारित प्रशासन पर केंद्रित हैं, जो सरकार के विजन को साकार करने में सहायक होंगी। साथ ही कस्टम प्रक्रियाओं के सरलीकरण और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। सदस्य (आईटी, करदाता सेवाएं एवं प्रौद्योगिकी) ने निर्यात-आयात से जुड़े सभी हितधारकों और सरकारी एजेंसियों को जोड़ने वाले एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम के लाभ बताए। उन्होंने कहा कि इससे त्वरित क्लीयरेंस, बेहतर व्यवसायिक योजना और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा।



एफएक्यू जारी, वेबसाइट पर उपलब्ध

संयुक्त सचिव (कस्टम) ने जानकारी दी कि बजटीय पहलों को सरल भाषा में समझाने के लिए सीबीआईसी ने 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (FAQs) जारी किए हैं, जो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

हार्बर लाइन की एसी लोकल को जबरदस्त प्रतिसाद

16 दिनों में 6.40 लाख यात्रियों ने किया सफर
2.38 करोड़ रुपये की आय

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

हार्बर लाइन पर हाल ही में शुरू की गई एसी लोकल सेवाओं को यात्रियों से जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। 26 जनवरी से 10 फरवरी 2026 तक मात्र 16 दिनों में एसी लोकल ट्रेनों से कुल 6.40 लाख यात्रियों ने यात्रा की। यह प्रतिदिन



औसतन 40,017 यात्रियों का प्रभावशाली आंकड़ा है। इस अवधि में मध्य रेल ने एसी लोकल टिकटों की बिक्री से 2.38 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जो प्रतिदिन औसतन 14.90 लाख रुपये है। इसमें 1.79 करोड़ रुपये सीजन टिकटों से तथा 59 लाख रुपये यात्रा टिकटों से प्राप्त हुए।

टिकट जांच अभियान तेज

इस उल्लेखनीय प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि यात्री पारंपरिक नॉन-एसी प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की तुलना में अधिक आरामदायक और सुविधायुक्त एसी लोकल सेवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। वर्तमान में मध्य रेल कुल 94 एसी लोकल सेवाएं संचालित कर रहा है, जिनमें से 14 सेवाएं 26 जनवरी 2026 से हार्बर लाइन पर शुरू की गई हैं। अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने

के लिए मुंबई मंडल द्वारा एसी लोकल ट्रेनों और स्टेशनों पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। हार्बर लाइन (26 जनवरी-10 फरवरी 2026): इस अवधि में टिकट जांच टीमों ने हार्बर लाइन एसी लोकल में अनियमित यात्रा के 810 मामलों का पता लगाया और 25 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया।

भुसावल मंडल में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस

डीबीडी संवाददाता | भुसावल

भुसावल मंडल द्वारा 12 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रेरणादायक कार्यक्रम में रेलवे कर्मचारी, यूनिट प्रतिनिधि और माननीय अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सम्मान, समान अवसर और सशक्तिकरण का संदेश देना था।

वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति



कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक श्री पुनीत अग्रवाल और अपर मंडल रेल प्रबंधक (प्रशासन) श्री सुनील कुमार सुमन मौजूद रहे। अपर मंडल रेल प्रबंधक (तकनीकी) श्री ए. के. मीणा, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी तथा एसबीएफ कमेटी के अध्यक्ष श्री दिलीप खरात सहित अन्य वरिष्ठ शाखा अधिकारी भी उपस्थित थे। विशेष अतिथि के रूप में बीडीओ/भुसावल श्री डी. जी. जाधव ने कर्मचारियों को प्रेरणादायक संबोधन दिया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन

कार्यक्रम में 200 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न यूनिटों और एसोसिएशनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण रहा, जिसने सभी का मन मोह लिया। यह आयोजन भुसावल मंडल की समावेशी कार्यसंस्कृति और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

ज्ञान और संस्कृति का संगम है एमआयटी विश्वशांति गुरुकुल: पद्मश्री परशुराम गंगावणे

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

आधुनिकता के इस दौर में भारतीय ज्ञान परंपरा और समकालीन शिक्षा का संतुलित संगम प्रस्तुत करने वाली संस्था ही सच्चे अर्थों में राष्ट्रनिर्माण का कार्य करती है। यह विश्व पद्मश्री परशुराम गंगावणे ने उल्लेखित एमआयटी विश्वशांति गुरुकुल में नव-निर्मित 'विश्वधर्मी विश्वनाथ सभागृह' के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए।

संस्थापक के आशीर्वाद से संपन्न हुआ उद्घाटन



यह उद्घाटन माईसें एमआयटी शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष विश्वधर्मी शा. डॉ. विश्वनाथ दा. कराड एवं सौ. उषा विश्वनाथ कराड के शुभ आशीर्वाद से पद्मश्री परशुराम गंगावणे तथा माईसें एमआयटी की ट्रस्टी एवं महासचिव प्रा. स्वाती कराड-चाटे के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर पनवेल कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पूर्व संचालक राजेंद्र पाटील, एमआयटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय की परियोजना निदेशिका प्रा. प्रभा कासलीवाल, अण्णासाहेब टेकाळे, प्रधानाचार्या अंशु सक्सेना, अकादमिक हेड शीतल वर्मा तथा मार्केटिंग एवं ऑपरेशन्स हेड प्रा. के. सी. मिश्रा सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।

तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन

डीबीडी संवाददाता | भुसावल

भुसावल मंडल में 10 फरवरी 2026 तक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों को राजभाषा नीति और उसके प्रभावी अनुपालन के प्रति जागरूक करना था, ताकि वे अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कर सकें।



राजभाषा नीति पर विस्तृत मार्गदर्शन

कार्यक्रम के प्रारंभ में मंडल यात्रिक इंजीनियर एवं संपर्क राजभाषा अधिकारी श्री युनुस अंसार मकानु ने उप महाप्रबंधक (राजभाषा) मध्य रेलवे, डॉ. विभागीय गौरे का स्वागत किया। 12 फरवरी 2026 को डॉ. गौरे ने 'राजभाषा नीति' विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक के प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 की महत्वपूर्ण जानकारी सरल और व्यावहारिक ढंग से समझाई।

कार्यालयीन कार्य में हिंदी प्रयोग पर जोर

अपने संबोधन में डॉ. गौरे ने राजभाषा के प्रचार-प्रसार और कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को उपयोगी दिशा-निर्देश प्राप्त हुए, जिससे उनके कार्य कार्यालयों में हिंदी के अधिकाधिक उपयोग को समर्थन का मांग बताया और कर्मचारियों के प्रश्नों का समाधान भी किया। कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को उपयोगी दिशा-निर्देश प्राप्त हुए, जिससे उनके कार्य कार्यालयों में हिंदी के अधिकाधिक उपयोग को समर्थन का मांग बताया

मनमाड से आईआरसीटीसी की नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू 18 फरवरी 2026 को रवाना होगी 'टेम्पल ट्रेल्स ऑफ दक्षिण' भारत गौरव ट्रेन

डीबीडी संवाददाता | मुंबई/मनमाड

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने श्रद्धालुओं के लिए नई आध्यात्मिक पर्यटन पैकेज "टेम्पल ट्रेल्स ऑफ दक्षिण" की घोषणा की है। यह विशेष भारत गौरव ट्रेन 18 फरवरी 2026 को मनमाड स्टेशन से प्रस्थान करेगी। 12 रात और 13 दिनों की यह यात्रा दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान करेगी।



दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों के दर्शन

आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, मुंबई के समूह महाप्रबंधक श्री गौरव झा ने बताया कि विशेष रूप से डिजाइन की गई एसी और नॉन-एसी पर्यटक ट्रेन यात्रियों को मुरुडेश्वर, गुरुवायूर, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम और महाबलीपुरम जैसे प्रमुख स्थलों तक ले जाएगी। श्रद्धालु मुरुडेश्वर शिव मंदिर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल और महाबलीपुरम के ऐतिहासिक मंदिरों सहित कई आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे।

ऑल-इन्क्लूसिव पैकेज की सुविधा

यह यात्रा ऑल-इन्क्लूसिव पैकेज के तहत संचालित की जा रही है, जिसमें रेल यात्रा, बजट होटलों में ठहराव (डबल/ट्रिपल/क्वाड शेयरिंग), शुद्ध शाकाहारी भोजन, एसी/नॉन-एसी स्थानीय परिवहन, दर्शनीय स्थल भ्रमण, यात्रा बीमा और आईआरसीटीसी टूर मैनेजर की सेवाएं शामिल हैं। आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र के जनसंपर्क अधिकारी डॉ.

ए. के. सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। यात्रा का किराया इकोनॉमी क्लास के लिए 23,370, स्टैंडर्ड 3उपरी के लिए 36,990 और कम्फर्ट 2एसी के लिए 48,760 निर्धारित किया गया है। बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर आईआरसीटीसी के पर्यटन पोर्टल पर उपलब्ध है।



मेष राजकीय सहयोग मिलेगा। रुके कार्य पूर्ण होंगे। अद्यात्म में रुचि रहेगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उचित लाभ हो सकेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। जीवनसाथी की उन्नति सामाजिक सम्मान को बढ़ाएगी।

वृष योजना फलीभूत होगी। घर-बाहर पुछ-परख बढ़ेगी। कार्यसिद्धि होगी। व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ने से व्यापारिक लाभ अधिक होने के योग हैं। यात्रा में सावधानी रखें। जल्दबाजी एवं लापरवाही से कार्य करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाएँ।

मिथुन आर्थिक समस्या रह सकती है। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खर्च का बोझ बढ़ेगा। चोट व दुर्घटना से बचें। लेन-देन में सावधानी रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। विवाद न करें।

मीन माता-पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दिन प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होगा। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। रुका पैसा प्राप्त होने के योग हैं। शोक समाचार मिल सकता है। भाग्यदोष अधिक होगी। थकान रहेगी। वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

कर्क बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा सफल रहेगी। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। जोखिम न लें। आवास संबंधी समस्या रहेगी। रचनात्मक कार्यों का प्रतिफल मिलेगा। पूर्व में किए गए कार्यों का शुभ फल प्राप्त हो सकेगा। स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी।

सिंह मित्रों की मदद से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने के आसार हैं। साझेदारी में नए प्रस्ताव मिलेंगे। फालतू खर्च होगा। तनाव रहेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें, बाकी सामान्य रहेगा। आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी।

कन्या नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी। रोजगार में वृद्धि होगी। यात्रा सफल रहेगी। प्रसन्नता बनी रहेगी। अपने व्यसनो पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्रम अधिक करना होगा। आपके कार्यों की समाप्ति एवं परिवार में आलोकना हो सकती है। व्यापार सामान्य चलेगा।

तुला राजकीय सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। थकान रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। विवाद से बचें। नए कार्यों में लाभ होने की संभावना है। परिवार की तत्कालीन आवश्यकताओं पर विश्वास रखते हुए कार्य करना चाहिए।

वृश्चिक रोजगार में वृद्धि होगी। संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं। बड़ा लाभ होगा। जल्दबाजी न करें। प्रमाद से बचें। दूरदर्शिता एवं बुद्धिमानी से कई रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। खर्चों में कमी करना होगी।

धनु पाटी व फिकनिक का आनंद मिलेगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। दिन प्रतिकूल रह सकता है। सामाजिक स्तर में परिवर्तन एवं प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित रहेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा।

मकर रुके कार्य पूर्ण होंगे। मेहनत सफल रहेगी। घर-बाहर पुछ-परख रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। नई योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। बड़े लोगों से भेंट होगी, जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा। शत्रु परास्त होंगे। आलस्य से बचकर रहें।

कुंभ पुराने मित्र व संबंधी मिलेंगे। अच्छी खबरें मिलेंगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। पारिवारिक वातावरण सहयोगात्मक रहेगा। आपकी बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान संभव है। सुख-समृद्धि बढ़ेगी।

कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का रहस्य

वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं, संवेदनशीलता और मानसिक स्थिरता का कारक ग्रह माना गया है। यह केवल आकाश में चमकने वाला ग्रह नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर उठने वाले विचारों, कल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं का सूक्ष्म संचालक है। जब चंद्रमा जन्मकुंडली के तीसरे भाव में स्थित होता है, तब उसका प्रभाव पारंपरिक ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार तीसरा भाव 'पराक्रम भाव' कहलाता है। यह भाव मनुष्य की इच्छाशक्ति, प्रयास, जोशिम लेने की क्षमता और अभिव्यक्ति की शक्ति को दर्शाता है। ज्योतिषाचार्य पं. भरतलाल शास्त्री जी के अनुसार तीसरे भाव में चंद्रमा जातक को कुशल संचारक, कलात्मक प्रवृत्ति वाला और साहसी बना सकता है, परंतु इसके साथ मानसिक अस्थिरता



प्रियंका जैन 9769994439

करती है। वे यात्राओं के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं और नए विचारों को अपनाने में संकोच नहीं करते। तीसरे भाव का संबंध लघु प्रवास से भी है, इसलिए ऐसे जातक जीवन में कई छोटी यात्राएं करने में हो या रहू-केतु या शनि से पीड़ित हो। पिता की आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि तीसरा भाव प्रयास और कर्म से जुड़ा है। यदि यहां चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो, तो परिवार में आर्थिक उतार-चढ़ाव देखे जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तीसरे भाव को 'काम त्रिकोण' का हिस्सा भी माना गया है, जिसमें तीसरा, सातवां और ग्यारहवां भाव सम्मिलित हैं। यह त्रिकोण इच्छाओं, संबंधों और सामाजिक विस्तार से जुड़ा है। यदि चंद्रमा यहां असंतुलित हो, तो व्यक्ति को इच्छाएं अधिक हो सकती हैं और मानसिक संतुष्टि कम मिल सकती है। अतः इस स्थिति में मन को संतुलित रखना अत्यंत आवश्यक है।

बीफ न्यूज

विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पेश



लखनऊ। उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 और राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2026 को प्रस्तुत किया गया। बजट सत्र के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने दोनों विधेयकों को सदन के पटल पर रखते हुए पुनः स्थापित करने की अनुमति मांगी, जिसे बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। मंत्री ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचे को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन संशोधनों से उच्च शिक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाली सुदृढ़ होगी और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा।

गंगा स्नान के दौरान डूबा झारखंड का युवक



वाराणसी। भेलपुर थाना क्षेत्र के केदारघाट पर गुरुवार सुबह गंगा स्नान के दौरान झारखंड के एक 18 वर्षीय युवक की डूबकर मौत हो गई। घनबाद निवासी आयुष कुमार परिवार के साथ काशी दर्शन के लिए वाराणसी आया था। स्नान के दौरान वह गहरे पानी में फिसल गया और डूबने लगा। सूचना मिलते ही गोताखोरों और जल पुलिस ने तलाश अभियान चलाया और युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अचानक हुई इस घटना से परिवार में मातम छाया हुआ है।

यूपी पंचायत चुनाव टलना तय यूपी: 12 लाख करोड़ का निवेश, 15 लाख को रोजगार

ओबीसी आयोग का गठन और उसकी रिपोर्ट के बाद चुनाव कराएगी योगी सरकार

योगी सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दिया हलफनामा

एजेंसी | नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव का टलना तय माना जा रहा है। चुनाव की तैयारियों के बीच योगी सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हलफनामा देते हुए बताया कि एक समर्पित पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के बाद चुनाव कराए जाएंगे। जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। दरअसल, हाईकोर्ट में दखिल याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि नए समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत सौदों का आरक्षण तय किया जाएगा।



ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनाव

यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उठाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों से पहले समर्पित आयोग का गठन जरूरी बताया गया है। प्रदेश का मौजूदा ओबीसी आयोग अक्टूबर 2025 में अपना मूल कार्यकाल पूरा कर चुका है। हालांकि सरकार ने इसका कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया है, लेकिन कानूनी तौर पर उसे समर्पित आयोग के अधिकार नहीं मिले हैं, जिस पर सवाल उठे थे। अब नया आयोग पिछड़े वर्गों का 'रैपिड सर्वे' करेगा, जिससे उनकी वास्तविक आबादी का आकलन कर आरक्षण तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक स्थानीय निकाय चुनाव से पहले तीन साल के कार्यकाल वाला समर्पित आयोग जरूरी है। सरकार का कहना है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव होगा।

सियासी गलियारों में क्या है

वहीं राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की चुनावी रणनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराने को लेकर नेगेटिव फीडबैक है। पार्टी के कई नेताओं को आशंका है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रधान से लेकर जिला पंचायत के चुनाव तक पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता आपस में लड़ेंगे। ऐसे नेताओं को आशंका है कि पंचायत चुनाव में किसी एक कैडिडेट का समर्थन करने से विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के एक वर्ग की नाराजगी उठाने का खतरा है। इसलिए ये बात चल रही है कि पहले विधानसभा हो जाए, फिर तनावपूर्ण पंचायत चुनाव की बिसात बिछे। ऐसे में अब पंचायत चुनाव का टलना लाभगय तय माना जा रहा है। प्रदेश में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मई के पहले समाप्त हो जाएगा। वहीं, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का पांच साल का कार्यकाल जुलाई के पहले समाप्त हो पूरा होगा। ऐसे में यदि समय पर चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों की जगह वहां सरकार की ओर से किसी सक्षम अधिकारी को रिस्वीर (प्रशासक) नियुक्त किया जाएगा।

पिछले पंचायत चुनाव 4 चरणों में हुए थे

यूपी में 57 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, जिला पंचायत वार्ड 3051, जिला पंचायत 75, क्षेत्र पंचायत 826 हैं। पिछले पंचायत चुनाव कोरोना लहर के बीच साल 2021 चार चरणों में हुए थे। पहले चरण में 18 जिले, दूसरे और तीसरे चरण में 20-20 जिले, और चौथे चरण में 17 जिलों में चुनाव हुए थे।

धरातल पर उतरीं चार लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं

सूबे में निवेश और रोजगार पर सरकार का दावा, सदन में हुई चर्चा

एजेंसी | नई दिल्ली

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदेश में निवेश और रोजगार को लेकर सदन में विस्तृत चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी की सदस्य डॉ. गगिनी के प्रश्न के उत्तर में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता 'नंदी' की ओर से सरकार का पक्ष रखा गया, जबकि अस्हमति जताए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विस्तृत जानकारी दी। खन्ना ने बताया कि निवेश प्रक्रिया तीन चरणों—एमओयू, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और परियोजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन—से होकर गुजरती है। उनके अनुसार प्रदेश में अब तक 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है।



EPFO पंजीकरण 40 लाख के ऊपर

उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले जहां लगभग 21 लाख पंजीकरण थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 40 लाख से अधिक हो गई है। औद्योगिक वृद्धि दर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय औसत 11.9 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह करीब 25 प्रतिशत दर्ज की गई है।

प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पर जवाब

निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर उठे सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि निजी उद्योग अपनी आवश्यकता के अनुसार नियुक्तियां करते हैं। सरकार के अनुसार निवेश और रोजगार के उपलब्ध आंकड़े प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व ही राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है।

जिनमें से करीब चार लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। इससे 15 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया।

गवालटोली लैंबॉर्गिनी कांड: सरकारी भूमि पर बना मंदरसा ढहा शिवम मिश्र गिरफ्तार

का न पुर। गवालटोली इलाके में लैंबॉर्गिनी कार से हुए हाई-प्रोफाइल हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। तंबाकू कारोबारी के.के. मिश्रा के पुत्र शिवम को गुरुवार सुबह आर्य नगर स्थित आवास से दबोचा गया और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिवम की गिरफ्तारी के लिए पांच विशेष टीमें लगाई गई थीं। उसके कानपुर में मौजूद होने की पुख्ता सूचना मिलते ही घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के समय उसके हाथ में मेडिकल उपकरण (जौग) लगा हुआ था और उसे सहारा देकर कोर्ट परिसर तक ले जाया गया।



उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर ने हटाया अतिक्रमण

रास्ते की भूमि पर बने मकानों पर भी चलेगा बुलडोजर

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बनिखटेर क्षेत्र के नरौली नगर पंचायत में अवैध रूप से निर्मित एक मंदरसे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह मंदरसा करीब 285 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जंच में यह भी सामने आया कि खाद के गड्डे और सावजनिक रास्ते की जमीन पर 8 से 10 मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं। इन निर्माणों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।



भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला अभियान

कार्रवाई के दौरान चंडौसी के उपजिलाधिकारी आशुतोष तिवारी, नायब तहसीलदार सतेंद्र चाहर और क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार सिंह मौके पर मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

उपजिलाधिकारी आशुतोष तिवारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई खाद के गड्डे की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने के उद्देश्य से की गई है और आगे भी सरकारी जमीन पर कब्जा पाए जाने पर इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे।

अग्रवाल ब्रदर्स की 5.25 करोड़ की संपत्ति सीज

कोडीन सिरप तस्करी प्रकरण में बड़ी कार्रवाई

वाराणसी पुलिस ने बैंक खाता भी किया फ्रीज

एजेंसी | कानपुर

कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े मामले में वाराणसी कमिश्नरेंट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अग्रवाल ब्रदर्स के मालिक विनोद अग्रवाल की करीब 5.25 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध से अर्जित धन के उपयोग की पुष्टि होने के बाद की गई। पुलिस के अनुसार, कानपुर के सिविल लाइंस, बिरहाना रोड, जाजमऊ और देहली सुजानपुर क्षेत्र में स्थित कुल पांच अचल संपत्तियों पर रोक लगाई गई है।



फर्जी लेनदेन कर की गई सप्लाई

एसीपी सारनाथ विदुष सकसेना ने बताया कि वाराणसी में दर्ज मुकदमों की विवेचना के दौरान खुलासा हुआ कि एमके हेल्थ केयर प्रयागराज और डीपी फार्मा सारनाथ के नाम से फर्जी लेन-देन कर कोडीन सिरप की सप्लाई दर्शाई गई, जबकि वास्तव में कोई माल नहीं भेजा गया। तस्करी से प्राप्त धन विभिन्न खातों के जरिए घूमकर वापस अग्रवाल ब्रदर्स तक पहुंचा।

अन्य राज्यों के लिए फर्जी बिलिंग

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी फर्जी बिलिंग के जरिए अन्य राज्यों में कोडीन युक्त सिरप की आपूर्ति दिखाता था। इस पूरे नेटवर्क में मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिलने पर संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई।

उल्लेखनीय है कि नवंबर 2025 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की छापेमारी के दौरान विनोद अग्रवाल फरार हो गया था। बाद में उसे जनवरी 2026 में हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है।

व्यापार जगत

CCIA ने इंटेल पर टोका 27.38 करोड़ का जुर्माना

वारंटी नीति में भेदभाव के मामले में की गई अमेरिकी कंपनी पर कार्रवाई

एजेंसी | नई दिल्ली

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रोसेसर से जुड़ी वारंटी नीति में भेदभाव बरतने के मामले में अमेरिकी सीमीकंडक्टर कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन पर 27.38 करोड़ रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। आयोग ने इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत बाजार में दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग का मामला माना है। सीसीआई ने इंटेल को निर्देश दिया है कि वह भारत-केंद्रित इस वारंटी नीति को वापस लेने की जानकारी का व्यापक प्रचार करे और अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे।



आठ साल तक प्रभावी रही विवादित नीति

आयोग ने बताया कि यह विवादित नीति लगभग आठ वर्षों तक प्रभावी रही। इसी अवधि को आधार बनाकर इंटेल के औसत प्रासंगिक कारोबार के आठ प्रतिशत के बराबर जुर्माना तय किया गया। हालांकि, एक अप्रैल 2024 से इस नीति को वापस लिए जाने को ध्यान में रखते हुए अंतिम जुर्माना घटाकर 27.38 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया।

आईटी शेयर्स की आंधी में बाजार धराशायी, 2.69 लाख करोड़ डूबे

एजेंसी | नई दिल्ली

वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और आईटी सेक्टर में मची तेज बिकवाली ने गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार की रफ्तार थाम दी। दिनभर उतार-चढ़ाव के बीच बिकवालों का दबदबा बना रहा, जिसके चलते प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। कारोबार समाप्त होने पर सेंसेक्स 0.66 प्रतिशत और निफ्टी 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा चोट आईटी सेक्टर को लगी। आईटी कंपनियों के शेयरों में आई टीसी गिरावट के कारण निफ्टी आईटी इंडेक्स 5.51 प्रतिशत टूट गया, जो मार्च 2020 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, मीडिया और रियल्टी के साथ बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, हेल्थकेयर, मेटल और पीपेस्क्रू शेयरों में भी कमजोरी दर्ज की गई। हालांकि कंप्यूटर हार्डवेयर और कैपिटल गुड्स सेक्टर में सीमित खरीदारी देखने को मिली।

विप्रो को सबसे ज्यादा नुकसान



आज के कारोबार में बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और आयशर मोटर्स जैसे शेयरों ने मजबूती दिखाई, जबकि टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो आईटी सेक्टर की कमजोरी के चलते सबसे ज्यादा नुकसान में रहे।

700 अंक फिसला सेंसेक्स

सेंसेक्स कारोबार के दौरान 700 अंकों से ज्यादा फिसला और अंत में 558.72 अंक टूटकर 83,674.92 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन के निचले स्तर से कुछ संभलते हुए 146.65 अंक की गिरावट के साथ 25,807.20 पर बंद हुआ।

472.30 लाख करोड़ घटी पूंजी

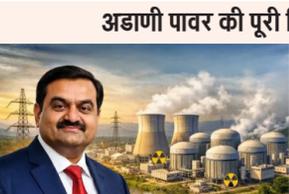
बाजार की इस गिरावट का असर निवेशकों की संपत्ति पर भी साफ दिखा। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण घटकर 472.30 लाख करोड़ रुपये रह गया, जिससे निवेशकों को एक ही दिन में करीब 2.69 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। ब्रॉडर मार्केट भी दबाव में रहा। बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.47 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.64 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ। कारोबार के दौरान बीएसई में 2,527 शेयरों में गिरावट जबकि 1,680 शेयरों में तेजी दर्ज की गई।

अडाणी समूह की परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एंट्री

नई अनुषंगी कंपनी का गठन

एजेंसी | नई दिल्ली

अडाणी समूह ने ऊर्जा क्षेत्र में अपने विस्तार को आगे बढ़ाते हुए परमाणु बिजली कारोबार में कदम रख दिया है। समूह की प्रमुख कंपनी अडाणी पावर लिमिटेड ने इस उद्देश्य से 'अडाणी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड' नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई की स्थापना की है।



अडाणी पावर की पूरी हिस्सेदारी

कंपनी की ओर से शेयर बाजार को दी गई सूचना के अनुसार नई इकाई का गठन परमाणु और नाभिकीय ऊर्जा से बिजली की उत्पादन, पररेषण और वितरण के लिए किया गया है। अडाणी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी पांच लाख रुपये रखी गई है, जिसे 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 50 हजार शेयरों में विभाजित किया गया है। इस कंपनी में अडाणी पावर की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। अडाणी पावर ने बताया कि नई कंपनी का पंजीकरण 11 फरवरी 2026 को किया गया और उसी दिन केंद्रीय पंजीकरण केंद्र से निगमण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। चूंकि यह इकाई पूरी तरह अडाणी पावर के स्वामित्व में है, इसलिए इसे संबंधित पक्ष इकाई के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इसके माध्यम से समूह परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराया।

जनवरी में खुदरा महंगाई दर 2.75% पर

नई दिल्ली। महंगाई के मोर्चे पर आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) श्रृंखला के तहत जनवरी माह में खुदरा महंगाई दर 2.75 प्रतिशत दर्ज की गई है। सरकार ने महंगाई आकलन के लिए आधार वर्ष में बदलाव करते हुए 2012 के स्थान पर 2024 को नया बेस ईयर निर्धारित किया है, जिसके आधार पर ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नई सीपीआई श्रृंखला में उपभोग के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं और सेवाओं के दायरे का विस्तार किया गया है। इसमें वस्तुओं की संख्या 259 से बढ़कर 308 और सेवाओं की संख्या 40 से बढ़कर 50 कर दी गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 2.73 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 2.77 प्रतिशत रही, जबकि खाद्य पदार्थों की महंगाई राष्ट्रीय स्तर पर 2.13 प्रतिशत दर्ज की गई। आवास से जुड़ी महंगाई 2.05 प्रतिशत रही।

फिलहाल नियंत्रण में महंगाई

NSO ने बताया कि जनवरी में खाद्य महंगाई सीमित दायरे में रही और ग्रामीण क्षेत्रों में यह शहरी इलाकों की तुलना में कुछ कम दर्ज की गई, जिससे संकेत मिलता है कि कुल मिलाकर महंगाई फिलहाल नियंत्रण में है। नई श्रृंखला में ग्रामीण मकान किराया, सीएनजी-पीएनजी जैसे ईंधन, ऑनलाइन मीडिया सेवाओं और ओटीटी सब्सक्रिप्शन को भी शामिल किया गया है, ताकि वास्तविक खर्च का अधिक सटीक आकलन किया जा सके। गौरतलब है कि नई सीपीआई का दांचा घरेलू उपभोग वय सर्वेक्षण 2023-24 पर आधारित है। पुरानी श्रृंखला (2012 आधार वर्ष) के तहत जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई 4.26 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जबकि दिसंबर 2025 में यह 1.33 प्रतिशत रही थी।

ICAI को नया नेतृत्व, प्रसन्न कुमार डी बने चेयरमैन

नई दिल्ली। देश की शीर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को नए सत्र के लिए नया अध्यक्ष मिल गया है। गुरुवार को हुई 26वीं परिषद की बैठक में प्रसन्न कुमार डी को वर्ष 2026-27 के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना गया। वहीं मंगेश पांडुरंग किनारे को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। आईसीएआई की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रसन्न कुमार डी इससे पहले उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे और अब वे संस्थान के 74वें अध्यक्ष बने हैं। वर्ष 1984 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले प्रसन्न कुमार डी आईसीएआई के विभिन्न मंचों पर कई अहम दायित्व निभा चुके हैं और पेशेवर क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है। गौरतलब है कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान देश में लेखा और ऑडिट पेशे की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसके अंतर्गत 15 लाख से अधिक सदस्य और विद्यार्थी पंजीकृत हैं। संस्थान का नेटवर्क देशभर में पांच क्षेत्रीय परिषदों और 185 शाखाओं तक फैला है, जबकि विदेशों में इसके 54 अध्यक्ष और 31 प्रतिनिधि कार्यालय कार्यरत हैं।

श्रीलंका की टी-20 में दूसरी सबसे बड़ी जीत

इटली की टी-20 वर्ल्ड कप में पहली जीत

न्यूज ब्रीफ अमेरिका के लिए करो या मरो का मैच

► ग्रुप बी के मैच में ओमान को 105 रन से करारी शिकस्त दी
► कुसल मंडिस-रत्नायके और शनाका ने जमाए जोरदार अर्धशतक

मंडिस-रत्नायके की मजबूत नींव

कुसल मंडिस ने 45 गेंदों पर 61 रन बनाकर पारी को स्थिरता दी। उनकी सात चौकों से सजी पारी संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण रही। उन्होंने स्पिनरों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया और पवन रत्नायके के साथ 52 गेंदों में 94 रन की अहम साझेदारी की। आयरलैंड के खिलाफ नाकाम रहे 23 वर्षीय रत्नायके ने इस बार 28 गेंदों पर 60 रन टोकते हुए अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 24 गेंदों में पचासा पूरा किया, जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल रहा।



शीर्ष पर लंका

श्रीलंका की यह लगातार दूसरी जीत है जिससे वह चार अंक लेकर ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंच गया है। ओमान को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। पवन प्लेयर ऑफ द मैच पवन रत्नायके ने 28 बॉल पर 60 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद पवन रत्नायके ने कहा, मुझे रिपन के खिलाफ खेलना पसंद है।

शनाका का तूफान, आखिरी ओवरों में 65 रन

असली तूफान पारी के अंतिम ओवरों में देखने को मिला। कप्तान दासुन शनाका ने महज 19 गेंदों में अर्धशतक जमाकर नया श्रीलंकाई रिकॉर्ड बना दिया। 20 गेंदों पर 50 रन की उनकी पारी में दो चौके और पांच गगनचुंबी छक्के शामिल थे। नदीम खान और सुफ़यान महमूद पर लगातार प्रहार करते हुए उन्होंने मैच की दिशा पूरी तरह बदल दी। कामिंदु मंडिस ने भी अंत में लगातार दो छक्के लगाकर स्कोर 225 तक पहुंचाया। आखिरी चार ओवरों में बने 65 रन ओमान के लिए निर्णायक साबित हुए।

नदीम का संघर्ष बेकार, श्रीलंकाई गेंदबाज हवी

मोहम्मद नदीम ने जरूर 56 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाकर संघर्ष किया और अपना तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया। वसीम अली (27) के साथ उन्होंने 42 रन की साझेदारी की, लेकिन दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला। पूरी टीम नौ विकेट पर 120 रन ही बना सकी। श्रीलंका के लिए दुष्प्रत चामीरा और महीश तीक्ष्णा ने दो-दो विकेट लिए, जबकि अन्य गेंदबाजों ने सही हुई लाइन-लेंथ से दबाव बनाए रखा और ओमान को मैच से बाहर कर दिया।

शनाका का रिकॉर्ड

कप्तान दासुन शनाका ने केवल 19 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया जो श्रीलंका की तरफ से टी-20 विश्व कप में रिकॉर्ड है। इससे पहले भी श्रीलंका की तरफ से सबसे तेज टी-20 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड शनाका के नाम ही था जो उन्होंने 2023 में भारत के खिलाफ बनाया था। विध्वंसक डेथ ओवर श्रीलंका ने अंतिम पांच ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 79 रन जोड़े। यह इस विश्व कप में अब तक डेथ ओवरों में बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है।

► नेपाल को 10 विकेट से हराया
► मोस्का ब्रदर्स की शतकीय साझेदारी, दोनों ने फिफ्टी लगाई

मुंबई: इटली की टीम को टी20 विश्व कप में अपनी पहली जीत मिल गई है। टीम पहली बार ही टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। पहले मैच में स्कॉटलैंड से हारने के बाद उसने दूसरे मुकाबले में नेपाल के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर इटली ने 10 विकेट से नेपाल को हराया। टी20 शैकम में नेपाल की टीम 16वें तो इटली 26वें नंबर पर है। पहले खेलते हुए नेपाल की पारी सिर्फ 123 रनों पर सिमट गई। इटली के लिए दो भाई जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का सलामी बल्लेबाज करने उतरे और उन्होंने टीम को 13वें ओवर में बिना विकेट खोए जीत दिला दी।

जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का ने दिलाई जीत



इटली के लिए दो भाई जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने आते ही अटक कर दिया और नेपाल को कोई मौका नहीं दिया। पहले ओवर में करन केसी के खिलाफ एंथनी ने छक्का लगाया। तीसरे ओवर में जस्टिन ने एक छक्का और दो चौके मारे। पावरप्ले में ही दोनों ने टीम को 68 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर जस्टिन और 5वीं गेंद पर एंथनी ने अपनी फिफ्टी पूरी की। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर इटली ने मैच को अपने नाम कर लिया। 44 गेंद पर 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से जस्टी मोस्का ने 60 रन बनाए। एंथनी ने 32 गेंद पर 3 चौके और 6 छक्के मारे और 62 रन बनाए।

पल्लीकल। ओमान पर 105 रन की बड़ी जीत के साथ श्रीलंका ने टी-20 विश्व कप में अपनी दावेदारी जोरदार अंदाज में पेश की। रनों के अंतर से यह टी-20 इतिहास में श्रीलंका की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इस प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ टीम ने सुपर आठ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। ग्रुप बी के इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर श्रीलंका ने पांच विकेट पर 225 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

घुड़दौड़: थंडरिंग फिनिक्स बेहतर

मुंबई। गुरुवार को महालक्ष्मी रेसकोर्स पर मुंबई घुड़दौड़ सत्र के 12वें दिन सात दौड़ों का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य दौड़ पी डी बोल्टन ट्रॉफी में नौ घोड़े हिस्सा ले रहे हैं। अधिराजसिंह जोधा प्रशिक्षित थंडरिंग फिनिक्स की स्थिति बेहतर है और उसके जीत की संभावना है। पहली दौड़ दोपहर 2.30 बजे आरंभ होगी। विभिन्न दौड़ों के लिए हमारे

चयन इस प्रकार है: 1- लारा (प्र.), एलेक्सेन्ड्रिया (द्वि.), 2- लेटियोस (प्र.), एवान्टे (द्वि.), 3- थंडरिंग फिनिक्स (प्र.), फोर्थ विंग (द्वि.), 4- मूगा (प्र.), क्रोमिसन पाइरेट (द्वि.), 5- व्हिस्पर (प्र.), ब्राइट बटन (द्वि.), 6- शानदार (प्र.), चेरुबाईन (द्वि.), 7- फॉक्सो (प्र.), एनफोर्स (द्वि.), दिन का सर्वोत्तम: थंडरिंग फिनिक्स।

कुलाबा बुल्स को खिताब



मुंबई। कुलाबा बुल्स की टीम ने फाइनल में कुलाबा शॉल्स को 2-0 से पराजित करके कुलाबा फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में चैंपियन होने का गौरव हासिल किया। कूपरेज मैदान पर खेले गए खिताबी मुकाबले में विजयी टीम की ओर से उसके अनुभवी खिलाड़ियों द्वारा संतुलित खेल का प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण पूरे मैच के दौरान उसकी पलड़ा भारी रहा। नितिन शेट्टी और गणेश तांडेले ने कुलाबा बुल्स के लिए गोल किया। प्रतियोगिता में कुल आठ टीमों ने हिस्सा लिया।



पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने स्मिथ

एजेंसी | कराची

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। चोटिल मिचेल मार्श के कवर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की विश्व टी-20 कप टीम में शामिल किए गए स्मिथ को नई फ्रेंचाइजी सियालकोट स्टेडियंस ने लगभग 5 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपये) में खरीदा। इस सीजन से पीएसएल में टीमों को संख्या छह से बढ़ाकर आठ कर दी गई है, जिससे प्रतिस्पर्धा और रोमांच दोनों बढ़ गए हैं।

पहली बार हुई नीलामी, ड्राफ्ट प्रणाली खत्म

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इस बार पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी प्रणाली लागू की है, जिसने पिछले एक दशक से चले आ रहे ड्राफ्ट प्रारूप की जगह ली। खिलाड़ियों की नीलामी बुधवार को लाहौर में आयोजित की गई। इस नीलामी में डेविड वॉनर, एडम जांगा, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मुस्ताफिजुर रहमान, डेवन कॉर्ने, राइली रूसो, तबरेज शम्सी, दासुन शनाका, कुसल मंडिस और मार्नस लाभुरेन जैसे कई विदेशी सितारे शामिल रहे। आठों फ्रेंचाइजियों ने कुल 103 खिलाड़ियों से अनुबंध किए।

नसीम शाह सबसे महंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी

तेज गेंदबाज नसीम शाह सबसे महंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी बने, जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8.65 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा। इसी टीम ने ऑलराउंडर फहीम अशरफ को 8.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में अपने साथ जोड़ा। बाबर आजम को पेशावर

जाल्मी ने सात करोड़ पाकिस्तानी रुपये में रिटेन किया, जबकि साइमन डेविल को 12.2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में बरकरार रखा गया। पीएसएल का आयोजन 26 मार्च से तीन मई तक होगा, जो इसी अवधि में भारत में होने वाले आईपीएल के साथ समानांतर चलेगा।

कनाडा और यूएई की निगाह पहली जीत पर

नई दिल्ली। अपने शुरुआती मुकाबलों में हार झेलने के बाद कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शुक्रवार को ग्रुप डी के मैच में पहली जीत की तलाश में उतरे। न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसी शीर्ष टीमों के साथ 'ग्रुप ऑफ डेथ' में शामिल होने के कारण दोनों टीमों के लिए सुपर आठ में जगह बनाना बेहद कठिन चुनौती है। ऐसे में यह मुकाबला उनके अभियान को परती पर लाने के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। कनाडा को अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से 57 रन से हार मिली, जबकि यूएई को न्यूजीलैंड ने 10 विकेट से शिकस्त दी। बड़े मुकाबलों का हालिया अनुभव नहीं होने का असर कनाडा के प्रदर्शन में दिखा।



मेगा बजट पर बनेगी एसएस राजामौली की

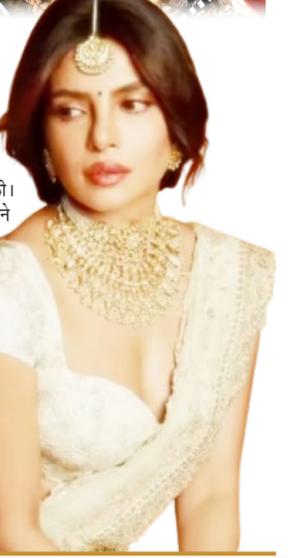
'वाराणसी'

बाहुबली फ्रेंचाइजी और आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से दुनियाभर में पहचान बनाने वाले निर्देशक एसएस राजामौली की अगली फिल्म 'वाराणसी' अब फिल्मों के बजट के मामले में भी इतिहास रचने को तैयार है। पहले ही फिल्म की 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होने की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, और अब इस प्रोजेक्ट के भारी-भरकम बजट को लेकर ताजा अपडेट आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'वाराणसी' का कुल बजट लगभग 1,361 करोड़ बताया जा रहा है, जिसके साथ यह भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है। 'वाराणसी' में प्रियंका चोपड़ा, साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म सिर्फ बड़े बजट की वजह से ही नहीं, बल्कि प्रियंका चोपड़ा की छह साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी के रूप में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले प्रियंका ने लंबे समय तक इस क्षेत्र से दूरी बना रखी थी, लेकिन अब 'वाराणसी' के साथ वे वापसी कर रही हैं, जिससे फैंस में ख़ास उत्साह है। फिल्म का बजट राजामौली की पिछली फिल्मों के स्तर से भी कई गुना अधिक है। उदाहरण के तौर पर, आरआरआर का बजट लगभग 651.6 करोड़ था, जो अपने समय में बड़े पैमाने पर बनने वाली फिल्मों में शामिल थी। लेकिन 'वाराणसी' ने विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन सीन और लोकेशन शूटिंग को ध्यान में रखते हुए उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 'वाराणसी' की शूटिंग भारत समेत 7 से अधिक देशों में की गई है, जिसमें अफ्रीका का केन्या भी शामिल है। विस्तृत लोकेशनों, बड़े बजट के एक्शन दृश्य और रोमांचक विजुअल इफेक्ट्स फिल्म को एक ग्लोबल सिनेमाई अनुभव प्रदान करेंगे। 'वाराणसी' को अब केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग की प्रस्तुति के नए मानक के रूप में देखा जा रहा है, जो कॉमर्शियल और कलात्मक दोनों स्तरों पर दर्शकों को प्रभावित करेगा।



प्रियंका चोपड़ा ने करियर, ट्रोलिंग और शादी पर तोड़ी चुप्पी

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने करियर और निजी जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं पर खुलकर बात की। उन्होंने उस दौर को याद किया जब उन्होंने हॉलीवुड में नई शुरुआत करने के लिए अपने स्थापित बॉलीवुड करियर को दांव पर लगा दिया था। प्रियंका ने बताया कि 30 की उम्र में सबकुछ छोड़कर फिर से शुरुआत करना बेहद डरावना फैसला था। भारत में वह आर्थिक रूप से सुरक्षित थीं और उनका नाम इंडस्ट्री में मजबूत था, लेकिन उन्होंने सीमाओं से परे जाकर काम करने का सपना चुना। उनके मुताबिक, वह सिर्फ दिखावे के लिए हॉलीवुड का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं, बल्कि ऐसे सिनेमा से जुड़ना चाहती थीं जिसकी कोई सरहद न हो। प्रियंका ने यह भी खुलासा किया कि हॉलीवुड में शुरुआती दिनों में उन्हें पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा। लोगों को उनके बारे में सीमित जानकारी होती थी और अक्सर उनकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता पर हैरानी जताई जाती थी।



ट्रोलिंग के बीच सलमान खान बने वरुण धवन का सहारा

वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' की सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन रिलीज से पहले उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग का सामना और आलोचनाएं भी हुईं। के अभिनय की जमकर उतार-चढ़ाव भरे दौर में '2' की सक्सेस खान करना पड़ा था। ट्रेलर आने के बाद उनके मुस्कुराने के अंदाज को लेकर कई मीम्स बने हालांकि फिल्म रिलीज होते ही माहौल बदल गया। दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने वरुण तारीफ की और इसे उनके करियर के बेहतरीन प्रदर्शनों में शुमार किया जा रहा है। इस सलमान खान का साथ वरुण के लिए बड़ा सहारा साबित हुआ। हाल ही में 'बॉर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस' के दौरान वरुण ने खुलासा किया कि ट्रोलिंग के समय सलमान ने उन्हें हौसला दिया था। वरुण ने कहा कि आजकल ट्रोलिंग एक ट्रेंड बन चुका है और वह ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेते। उन्होंने बताया कि जब उनकी मुस्कान पर मीम्स वायरल हो रहे थे, उसी दौरान रेत रात सलमान खान का फोन आया। वरुण के मुताबिक, वह बस हंस रहे थे और बोले - 'अच्छी चीजें होने वाली हैं।' उस वक्त उनका विश्वास भरे लिए बहुत मायने रखता था। वरुण ने आगे बताया कि फिल्म की सफलता के बाद सलमान ने दोबारा फोन कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, मैं आप सबके लिए बहुत खुश हूँ मुझे तुम पर गर्व है बेटा।' रात के दो बजे थे और मैं विस्तर पर उठ गया। यह मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक था। वरुण के अनुसार, सलमान आसानी से किसी की तारीफ नहीं करते, इसलिए उनके ये शब्द उन्हें लंबे समय तक प्रेरित करते रहेंगे।

देश में आसान नहीं सूचना मांगना

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, एमएचए समेत बड़े विभागों ने बड़ी संख्या में दुकराई आरटीआई

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024-25 में कई बड़े सरकारी संस्थानों ने बड़ी संख्या में सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन खारिज किए। इनमें दिल्ली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय सबसे ज्यादा आवेदन दुकराने वालों में शामिल रहे।

किस संस्था ने कितने आवेदन खारिज किए

विभिन्न संस्थानों द्वारा आरटीआई (RTI) आवेदनों को खारिज करने के आंकड़ों में काफी विविधता देखी गई है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने सबसे अधिक 22.88% (2,089 में से) आवेदन खारिज कर शीर्ष 20 संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13.73% और गृह मंत्रालय ने बड़े मंत्रालयों में सर्वाधिक 13.33% की दर से आवेदन अस्वीकार किए। वहीं, वित्त मंत्रालय ने 2.2 लाख से अधिक आवेदनों में से 8.50% को दुकराया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की अस्वीकृति दर 7.98% और कानून मंत्रालय की सबसे कम 7.14% रही।



अपीलों की संख्या भी ज्यादा

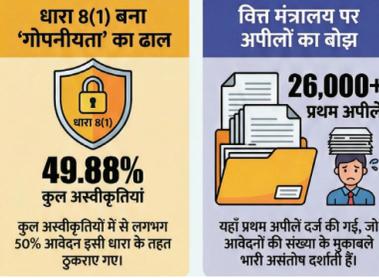
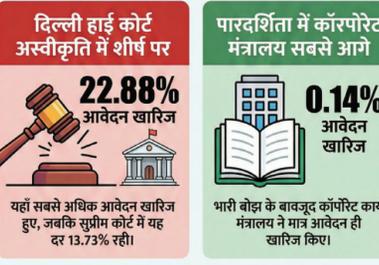
वित्त मंत्रालय- 26,219 प्रथम अपील, 3,966 दूसरी अपील
गृह मंत्रालय- 9,389 प्रथम, 960 दूसरी अपील
रक्षा मंत्रालय- 16,876 प्रथम, 1,203 दूसरी अपील

कम अस्वीकृति वाले विभाग

बड़े मंत्रालयों में आरटीआई आवेदनों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति काफी सकारात्मक रही है, जहाँ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 2,54,657 आवेदनों के विशाल भार के बावजूद केवल 0.14% आवेदन ही खारिज किए। इसी तरह, सड़क परिवहन मंत्रालय ने 0.70% और शिक्षा मंत्रालय ने मात्र 0.74% की न्यूनतम अस्वीकृति दर बनाए रखी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इन विभागों ने पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए भारी संख्या में प्राप्त आवेदनों में से बेहद कम को तकनीकी या कानूनी आधार पर दुकराया है। आरटीआई कानून की धारा 8(1), जो राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीय जानकारी, व्यापार रहस्य या निजी सूचना जैसी वजहों से जानकारी देने से छूट देती है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई।

RTI रिपोर्ट 2024-25: सूचना का अधिकार या इंकार?

सूचना देने के मामले में न्यायपालिका और गृह मंत्रालय की अस्वीकृति दर सबसे अधिक है।



सेना की बढ़ेगी ताकत

114 राफेल और 6 P-81 विमान खरीद को मंजूरी

3.25 लाख करोड़ रुपये का है रक्षा सौदा

वायुसेना को मिलेंगे 6 से 7 नए स्क्वाड्रन



नई दिल्ली। देश की सुरक्षा व्यवस्था को फुलप्रूफ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने एक ऐतिहासिक खरीद को मंजूरी दी है। परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों और नौसेना के लिए 6 P-81 पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमानों की खरीद के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा खरीद योजनाओं में से एक माना जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये बताई गई है।

इस सौदे का सबसे अहम पहलू वायुसेना की गिरती स्क्वाड्रन संख्या को संभालना है। 114 नए राफेल विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। वर्तमान में वायुसेना के पास लगभग 30 स्क्वाड्रन हैं, जबकि देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। डीएसी की मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिस्टीमेटि (सीसीएस) के पास भेजा जाएगा।

नौसेना की समुद्री निगरानी भी होगी मजबूत

आसमान के साथ-साथ समंदर में भी भारत की निगरानी क्षमता बढ़ने वाली है। इन नए डीएसी ने नौसेना के बेड़े में 6 नए P-81 एयरक्राफ्ट जोड़ने को मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना पहले से ही 12 P-81

विमानों का संचालन कर रही है। इन नए विमानों के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी एयरक्राफ्ट जोड़ने को मंजूरी दी है। (एंटी सबमरीन) क्षमता को और अधिक मजबूती मिलेगी।

न्यूज ब्रीफ

शेख हसीना ने बांग्लादेश चुनाव को फर्जी और अवैध करार दिया

ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवांमनी लीग ने चुनाव को फर्जी, अवैध और असंवैधानिक करार दिया। पार्टी ने जनता के मतदान अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान की भावना की अवहेलना का आरोप लगाया। अवांमनी लीग ने ट्वीट में कहा कि चुनाव की प्रक्रिया योजना बनाकर रची गई एक तमाशा थी, जिसमें पार्टी की भागीदारी नहीं थी। पार्टी ने जनता, माताओं, बहनों और अल्पसंख्यक समुदायों का धर्यावाद किया, जिन्होंने इस जबरदस्त फर्जी चुनाव को नकार दिया।

कर्नाटक भाजपा विधायक बिरथी बसवराज गिरफ्तार

बंगलुरु। कर्नाटक के भाजपा विधायक बिरथी बसवराज को गुरुवार को केम्पोगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वे अहमदाबाद से लौटने के बाद ही पुलिस की टीम द्वारा हिरासत में लिए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, केआर पुरम विधायक की गिरफ्तारी उस समय हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह याचिका उस मामले में थी जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था। गौरतलब है कि यह मामला शिवप्रकाश उर्फ बिकलू शिवा (40) की हत्या से जुड़ा है, जो 15 जुलाई 2025 को भारतीय नगर में लोहे की रॉड और कटारों से मार दिया गया था। हत्या के समय उसके सामने उसकी मां विजयलक्ष्मी मौजूद थीं। उन्होंने शिकायत में बताया कि उन्होंने देखा कि आठ से नौ लोग उनके बेटे पर हमला कर रहे थे। जब उसका मित्र बीच-बचाव करने आया, तो उसे भी लोहे की रॉड से मारा गया। जांच में पता चला कि इस हत्या का कारण फरवरी 2025 से लंबित जमीन विवाद था। इस विवाद में किशोरपुर क्षेत्र की भूमि पर कई प्रतिद्वंद्वी दावेदार शामिल थे। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान बिरथी बसवराज, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, को इस घटना में पांचवें आरोपी के रूप में नामित किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक की जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी शिवप्रकाश उर्फ बिकलू शिवा की हत्या के मामले में आरोपी बंगलुरु के भाजपा विधायक बसवराज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद उनके आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष आत्मसमर्पण करने की संभावना है। बंगलुरु स्थित सीआईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागवी की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि विधायक ने मामले के मुख्य आरोपी से अपने संबंधों को लेकर अलग दावे किए हैं। अदालत ने कहा, "आप एक जन्मप्रतिनिधि हैं, आपको मुकदमे का सामना करने का साहस दिखाना चाहिए।" इस घटनाक्रम के बाद सीआईडी ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

विमान से पक्षियों के टकराने की घटनाएं बढ़कर 1782 हुईं

एजेंसी | नई दिल्ली

देश के हवाई अड्डों पर विमानों से पक्षियों के टकराने (बर्ड हिट) की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2024 में ऐसी 1278 घटनाएं सामने आई थीं, जो पिछले वर्ष बढ़कर 1782 हो गईं। गुरुवार को लोकसभा में सरकार ने यह जानकारी दी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोत ने लिखित उत्तर में बताया कि पिछले पांच वर्षों में कुल 6337 बर्ड हिट की घटनाएं दर्ज की गईं।



विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डों पर कर्मियों को संभावित खतरों से निपटने के लिए नियम और दिशानिर्देश जारी किए हैं।

एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के 1279 पद खाली

सरकार ने यह भी बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) के स्वीकृत 5537 पदों में से 1279 पद फिलहाल रिक्त हैं। देश में एयर ट्रैफिक प्रबंधन का जिम्मा सरकारी कंपनी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के पास है, जो एकमात्र एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर है। मंत्री मोहोत के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में देश के सात ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटरों में 4320 एटीसी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भेनापार की कमी के बावजूद किसी भी प्रमुख ऑपरेशनल स्यूटि को बंद नहीं किया गया है।

तीन घंटे में हटानी होगी आपत्तिजनक सामग्री

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021, जिन्हें देश भर में आईटी नियम 2021 के नाम से जाना जाता है, में कुछ संशोधनों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने कई पुराने नियमों को न सिर्फ बदला है, बल्कि नए नियमों को भी जोड़ा है। इसके तहत अब पहली बार भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए बनाए गए कंटेन्ट और सिंथेटिक (संघादित किए गए ऑरिजनल कंटेन्ट) सामग्री को विनियमित करने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इन संशोधनों को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से सूचना-प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 87 के जरिए मिली ताकतों का इस्तेमाल करते हुए पेश किया गया है।

लोकसभा में बीजेपी सांसद ने किया राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश

सदस्यता रद्द और चुनाव न लड़ने की मांग

नई दिल्ली। भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने लोकसभा में एक मोशन पेश किया है, जिसमें विपक्षी नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। डॉ. दुबे ने कहा सरोस फाउंडेशन और देश को दुकड़े करने वाले ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी भारत का विभाजन करना चाहते हैं। इसलिए मैंने लोकसभा के नियम 352(5) और 353 के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने की पाबंदी का मोशन पेश किया लोकसभा नियम 352(5) और 353 के तहत संसद किसी सदस्य की सदस्यता रद्द करने या भविष्य के चुनावों में भाग लेने पर रोक लगाने की प्रक्रिया को अपनाती है यदि उसके कार्य संविधान और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हों।

भाजपा नेता ने दी राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति न करने की नसीहत



इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता वानाथी श्रीनिवासन ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अपील की कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति करना बंद करें और इसके बजाय रचनात्मक राजनीति

पर ध्यान दें। वानाथी श्रीनिवासन ने लोकसभा में कथित रूप से एक पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा को लेकर उत्पन्न हंगामे की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जानबूझकर देश की सुरक्षा के साथ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी, जिन्हें जनता ने नकार दिया है, लोकसभा में अराजकता पैदा कर रहे हैं। राजनीति में करने के लिए हजारों काम हैं, लेकिन वे अनावश्यक रूप से देश की सुरक्षा को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। इससे उनका विपक्षी नेता का पद भी खतरे में पड़ सकता है।

इमरान खान की आंख की रोशनी 85% खत्म



इस्लामाबाद। लंबे समय से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हेल्थ अपडेट से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान की दाहिनी आंख की रोशनी 85 फीसदी खत्म हो चुकी है। उसमें अब सिर्फ 15 फीसदी को रोशनी बची है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इमरान खान की आंख की जांच के लिए एक स्पेशल मेडिकल टीम बनाने का आदेश दिया है। यह आदेश कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें PTI फाउंडर ने दावा किया था कि उनकी दाहिनी आंख में "सिर्फ 15 फीसदी" रोशनी बची है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इमरान को उनके बच्चों से बात करने की इजाजत दी जाए। यह आदेश दिया गया कि आंखों की जांच और फोन कॉल दोनों 16 फरवरी (सोमवार) से पहले किए जाएं। SC का यह निर्देश तब आया जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस (CJP) याह्या अफरीदी की अगुवाई वाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सहित दो अन्य जजों की बेंच ने PTI संस्थापक के अदियाला जेल में रहने की स्थिति से जुड़े मामले की सुनवाई फिर से शुरू की।

खून का थक्का जमने से गई रोशनी

कोर्ट में पेश रिपोर्ट में बताया गया कि इमरान खान ने कहा है कि उनकी दाईं आंख की केवल लगभग 15% दृष्टि बची है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य थी, लेकिन बाद में धुंधलापन शुरू हुआ और इलाज में देरी के कारण स्थिति बिगड़ गई। बताया गया कि बाद में डॉक्टरों ने जांच में खून का थक्का (ब्लड क्लॉट) जैसी समस्या की पहचान की और इंजेक्शन सहित इलाज किया गया, लेकिन दृष्टि पूरी तरह वापस नहीं आ सकी।

शराब घोटाला मामले में फैसला सुरक्षित

केजरीवाल और सिसोदिया पर तय होंगे आरोप या नहीं, 27 फरवरी को फैसला

एजेंसी | नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोप तय करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सीबीआई और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया। अब इस नज़रें अदालत के फैसले पर टिकी है। देखा होगा कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर आरोप तय करने के आदेश देती है या नहीं। अदालत 27 फरवरी को अपना फैसला सुना सकती है। सीबीआई ने सबसे पहले 2022 में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद उसकी ओर से पूरक आरोप पत्र पेश किए गए थे। आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति को अपने पक्ष में करवाने के लिए शराब कारोबारियों की साउथ लॉबी की ओर से 100 करोड़ रुपये दिए गए थे।



आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत: सीबीआई

सीबीआई ने कहा कि साजिश के अपराध को पूरी तरह से देखा जाना चाहिए। आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। सीबीआई की तरफ से एएसजी डीपी सिंह और वकील मनु मिश्रा पेश ने अपनी दलीलों में कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए काफी सबूत और आधार मौजूद हैं।

केजरीवाल के खिलाफ आरोप कट-पेस्ट

वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने यह भी कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उनके साउथ लॉबी से पैसे लेने के अनुरोध से जोड़ता हो। केजरीवाल का नाम पहली चार्जशीट या उसके बाद की 3 पूरक चार्जशीट में नहीं था। उनका नाम चौथी पूरक चार्जशीट में आया। यह भी कहा गया कि चौथी चार्जशीट का विषय वही है जो पिछली चार्जशीट का था।

टकराव मुस्लिम संगठनों ने आदेश को बताया असंवैधानिक, कोर्ट जाने की ढी चेतावनी

'वंदे मातरम' पर रार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपत्ति

एजेंसी | नई दिल्ली

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी छंदों को आधिकारिक समारोहों में पहले गाने के आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। बोर्ड ने सरकार को इस आदेश को अविलंब वापस लेने की चेतावनी दी है, अन्यथा वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिसके लिए वह कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। यह प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी उस निर्देश के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय गीत वंदे

मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन एक साथ बजाए जाने पर वंदे मातरम के सभी छंद पहले गाने जाएंगे। 28 जनवरी के आदेश में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत गाने के लिए एक प्रोटोकॉल तय किया था। इसके अनुसार, राष्ट्रीय समारोहों जैसे राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराने और राज्यपालों के भाषणों वापस लेने की चेतावनी दी है, अन्यथा वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिसके लिए वह कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। यह प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी उस निर्देश के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय गीत वंदे



वंदे मातरम पर सरकार का आदेश आजादी पर हमला: मदनी

मुस्लिम संगठन जमीयत उल्लेमा-ए-हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि सरकार का ये आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। संगठन ने सरकार के आदेश को एकतरफा और मनमाना बताया।

धार्मिक और कानूनी आधार पर विरोध

बोर्ड के महासचिव मोलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजहिदी ने एक प्रेस बयान में कहा कि यह निर्णय मुसलमानों के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने तर्क दिया कि रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह और संविधान सभा की बहसों के बाद यह तय हुआ था कि वंदे मातरम के केवल पहले दो छंदों का ही प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी एक धर्म की मान्यताओं या शिक्षाओं को दूसरे धर्म के अनुयायियों पर जबरन नहीं थोप सकती।